PRGI No. UPHIN/25/A1698

नवसर्जन संस्कृति

नवसर्जन संस्कृति

PUBLISHED HIINDI DAILY FROM LUCKNOW

वर्ष : 02
अंक : 041
दि. 10.06.2026,
बुधवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

प्रधानमंत्री मोदी इतने सफल क्योंकि वह; पूर्व पीएम एचडी देवगौड़ा ने क्या बताया

(जीएनएस)।

पूर्व पीएम एच डी देवगौड़ा ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले, लोकतांत्रिक रूप से चुने गए प्रधानमंत्री बन गए हैं। उन्होंने नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। यह भारत में लोकतंत्र की मजबूती का प्रतीक है। 1947 से 2014 तक, भारत एक अलग देश बन गया है, आकार, विविधता और अर्थव्यवस्था में बड़ा बदलाव आया है। अब देश ज्यादा सवाल पूछने वाला, जुड़ा हुआ और परिपक्व हो गया है।

पीएम नरेंद्र मोदी अब भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले, लोकतांत्रिक रूप से चुने गए प्रधानमंत्री बन गए हैं। उन्होंने नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इससे भी अहम बात यह है कि यह इस बात का बड़ा सबूत है कि भारत में लोकतंत्र न सिर्फ बचा रहा, बल्कि फला-फूला भी। साल 1947 में, कई समान रूप से काबिल और समर्पित लोगों के बीच से नेहरू को देश का पहला प्रधानमंत्री चुना गया था और यह चुनाव असाधारण परिस्थितियों में हुआ था। असल में, जनता पर गांधीजी के नैतिक प्रभाव ने ही इस नियुक्ति को पक्का किया था। इसके बाद, नेहरू गांधीजी का आशीर्वाद और आजादी की लड़ाई की साख लेकर 1952 के पहले आम चुनाव में उतरे।

टाइम्स ऑफ इंडिया में लिखे अपने लेख में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री एच डी देवगौड़ा ने कहा कि उस समय, कांग्रेस पार्टी का एकछत्र राज था। उसे किसी राजनीतिक चुनौती का सामना नहीं करना पड़ा। हालांकि, आम चुनाव में 53 राजनीतिक पार्टियों ने हिस्सा लिया था, लेकिन उनकी मौजूदगी और असर बहुत कम था। उस दौर से लेकर 2014 में मोदी के पहली बार और 2024 में तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने तक, भारत एक बिल्कुल अलग देश बन गया। आकार, विविधता और अर्थव्यवस्था के मामले में तो यह लगभग पहचान में न आने लायक हो गया।

यह कहना बहुत आकर्षक है, हालांकि पूरी तरह समझदारी भरा नहीं, कि 2014 या 2024 की तुलना में 1952 में ढट चुना जाना आसान था। यहां तक कि जब मैं 1996 में ढट बना, तब तक हालात, राजनीतिक पैमाने और मुकाबला पूरी तरह बदल चुके थे। देश अब ज्यादा सवाल पूछने वाला, ज्यादा जुड़ा हुआ और ज्यादा परिपक्व हो गया था।

मेरा कार्यकाल ज्यादा लंबा नहीं था, मैं सिर्फ 11 महीने ही इस पद पर रहा और मुझे हैरानी होती है कि मोदी किस तरह बिना थके शीर्ष पर बने हुए हैं—न तो उनमें कोई थकान दिखती है और न ही उन्हें चुनने वाले लोगों में। पद पर रहते हुए उनकी सहनशक्ति और काम करने की क्षमता वाकई बहुत खास है।

आइए कुछ दिलचस्प आंकड़ों पर नजर डालें जो नेहरू के समय से अब तक आए बड़े बदलावों को दिखाते हैं। अगर सिर्फ राजनीतिक मुकाबले की बात करें, तो 1952 के चुनावों में मैदान में सिर्फ 53 पार्टियां थीं, जबकि 2024 में मोदी का मुकाबला 2,593 पार्टियों से था। नेहरू के समय मतदाताओं की संख्या 17 करोड़ थी, जो 2014 तक बढ़कर 83 करोड़ हो गई। भारत की आबादी, जो 1952 में

34 करोड़ थी, आज 146 करोड़ से ज्यादा है।

एक और बात जिसने मेरा ध्यान खींचा, वह यह है कि नेहरू की कैबिनेट में भारत की सामुदायिक, सांस्कृतिक और जातीय विविधता की झलक नहीं मिलती थी। यहां तक कि जब नेहरू प्रधानमंत्री के तौर पर अपने तीसरे और आखिरी कार्यकाल में थे, तब भी उनकी कैबिनेट में ज्यादातर ऊंची जाति के पुरुष ही थे। नेहरू ने काका केलकर कमीशन की रिपोर्ट को ठुकरा दिया था, जिसमें दबे-कुचले और पिछड़े वर्गों को आरक्षण देने की कोशिश की गई थी।

पीएम मोदी की मौजूदा कैबिनेट में बहुत विविधता है। इसमें 27 डइउ, 10 रउ और 5 रळ सदस्य हैं। महिलाओं की भागीदारी भी काफी बढ़ी है। मोदी ने अप्रैल 2026 में संसद की संख्या बढ़ाने का प्रस्ताव भी रखा है, ताकि महिलाओं को ऐतिहासिक प्रतिनिधित्व मिल सके और हमारा देश एक बेहतर संघ बन सके। उन्होंने महिला आरक्षण बिल पास करवाना पहले ही सुनिश्चित कर दिया है।

आज का भारत नेहरू के समय के भारत की तुलना में कहीं ज्यादा शोर-शराबे वाला और मुखर लोकतंत्र है। जाति के प्रति जागरूकता, संवैधानिक अधिकार, नागरिक अधिकार, जेंडर के प्रति जागरूकता और पर्यावरण से जुड़ी चिंताएं—इन सभी मामलों में जागरूकता का स्तर बहुत बढ़ गया है।

नेहरू के समय में भारत में ज्यादातर लोग अनपढ़ थे। साथ ही, लोगों को यह ठीक से पता नहीं था कि लोकतांत्रिक सरकार से क्या उम्मीद की जाए। यह एक नई व्यवस्था थी। आज के नागरिक, देश और लोकतंत्र की भलाई के लिए, ज्यादा पढ़े-लिखे और जागरूक हैं। उनकी नजर से कुछ भी नहीं बचता।

नेहरू को ज्यादा से ज्यादा आधा दर्जन अखबारों से निपटना पड़ता था, लेकिन मोदी को हर पल लाखों लोगों की नजर का सामना करना पड़ता है। ऐसा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की वजह से है, जहां आलोचना बिना जांच-परख के, अनुचित और बहुत कठोर व व्यक्तिगत भी हो सकती है। इसके अलावा, उन्हें मुख्यधारा की प्रेस की चौबीसों घंटे होने वाली आलोचना और कभी-कभी उनके विरोध का भी सामना करना पड़ता है। नेहरू के समय में टेलीविजन पर समाचार नहीं होते थे।

मैं पीएम मोदी को इस बात के लिए बधाई देता हूं कि उनकी देखरेख में भारत एक मजबूत लोकतंत्र बना हुआ है। भारत को सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बनाए रखने की उनकी कोशिश, उनकी कल्याणकारी

लखनऊ में 53 हजार किसानों की फार्मर रजिस्ट्री में आ रहीं दिक्कतें, आधार में पिता की जगह खुद का नाम

(जीएनएस)।

लखनऊ। मलिहाबाद के किसान राम संजीवन के पिता का नाम आधार में राम संजीवन ही लिखा है। ऐसे में उन्हें फार्मर रजिस्ट्री पोर्टल पर डेटा फीड करने में दिक्कतें आ रही हैं। पिता का नाम सही नहीं हो पा रहा, क्योंकि पिछले साल अगस्त में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) ने आधार में पिता का नाम लिखना बंद कर दिया है।

आधार में पिता का नाम तभी शामिल हो सकता है, जब पिता स्वयं आधार केंद्र जाकर बायोमीट्रिक सत्यापित करें। राम संजीवन के पिता दिवंगत हो चुके हैं। इसलिए वह आधार में संशोधन नहीं करा पा रहे।

उप निदेशक कृषि विनय कौशल ने बताया कि लखनऊ में 2.46 लाख किसानों को फार्मर रजिस्ट्री करानी है। इनमें से 1.93 लाख ने फार्मर रजिस्ट्री करा ली है, जबकि 53 हजार किसान अब विभिन्न कारणों से यह नहीं करा पाए हैं। इनमें राम संजीवन जैसे अनेक किसान चाह कर भी फार्मर रजिस्ट्री नहीं करा पा रहे हैं।

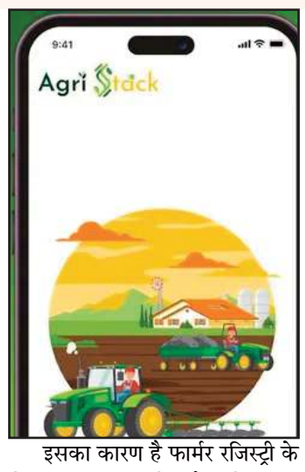

इसका कारण है फार्मर रजिस्ट्री के लिए आधार आधारित डेटा लिया जा रहा है, जबकि यूआइडीएआइ ने "सन आफ", "डाटर आफ" या "वाइफ आफ" जैसे शब्दों को हटाकर केवल 'केयर ऑफ' का विकल्प लागू कर दिया है। आधार में पिता या पति का नाम जुड़वाने या अपडेट करने के लिए आप 'हेड आफ फैमिली' आधारित पता अपडेट करने प्रक्रिया का उपयोग कर सकते हैं।

यूआईडीएआई के अनुसार आधार में "केयर आफ" में अब भी पिता का नाम लिखवा सकते हैं, लेकिन इसके लिए पिता को बायोमीट्रिक अपडेट कराने आधार केंद्र जाना होता है। जिनके पिता दिवंगत हैं, उनके पास इसका विकल्प नहीं है।

ये दिक्कतें भी आ रहीं

आधार कार्ड और खतौनी में नाम, पिता का नाम या स्पेलिंग में अंतर होने पर सिस्टम डेटा स्वीकार नहीं करता है। तकनीकी खामी के कारण पोर्टल पर खसरा और खतौनी की जानकारी (रकबा आदि) सही तरीके से सिस्टम में लोड नहीं हो पाती है।

एग्री स्टैक पोर्टल पर सर्वर डाउन या एरर होने से फार्मर रजिस्ट्री की प्रक्रिया बाधित होती है।

कई बार रजिस्ट्रेशन फार्म में आधार सत्यापन के लिए "सहमति" चेकबाक्स पर क्लिक ही नहीं होता, जिससे आगे की प्रक्रिया रुक जाती है।

यदि एक ही खतौनी या गाटे में कई किसानों के नाम दर्ज होते हैं तो उनकी अलग-अलग डिजिटल आइडी बनने में तकनीकी दिक्कतें आती हैं।

दिल्ली की सड़कों का होने वाला है डिजिटल इलाज! ट्रैफिक-जलभराव पर एक साथ वार करेगी रेखा सरकार की नई योजना

(जीएनएस)।

दिल्ली में ट्रैफिक जाम, टूटी सड़कें, धूल से होने वाला प्रदूषण और बरसात के दौरान जलभराव लंबे समय से लोगों की परेशानी का कारण रहे हैं। अब दिल्ली सरकार इन समस्याओं से निपटने के लिए एक ऐसी व्यवस्था तैयार कर रही है, जो सिर्फ गड्ढे भरने या सड़क मरम्मत तक सीमित नहीं होगी, बल्कि पूरी सड़क व्यवस्था को डिजिटल और वैज्ञानिक तरीके से मॉनिटर करेगी।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोमवार (09 जून) को इसकी जानकारी देते हुए कहा कि राजधानी में पहली बार रोड एसेट मैनेजमेंट सिस्टम (RAMS) विकसित किया जा रहा है।

दिल्ली की सड़कों के लिए नया ब्लूप्रिंट

सरकार ने इस परियोजना के लिए केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान (CSIR-CRRI) और स्कूल ऑफ

प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर (SPA) के साथ समझौता किया है। इस साझेदारी का मकसद दिल्ली की सड़कों के रखरखाव को पारंपरिक व्यवस्था से निकालकर डेटा आधारित और वैज्ञानिक मॉडल पर लाना है।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का कहना है कि तेजी से बढ़ते शहरीकरण और वाहनों की संख्या ने सड़क प्रबंधन को पहले से कहीं अधिक चुनौतीपूर्ण बना दिया है। ऐसे में अब सड़कों की स्थिति का रिकॉर्ड डिजिटल रूप में तैयार किया जाएगा और उसी आधार पर मरम्मत तथा रखरखाव की प्राथमिकताएं तय होंगी।

कैसे काम करेगा नया सिस्टम?

रोड एसेट मैनेजमेंट सिस्टम के तहत राजधानी की सड़कों का विस्तृत डिजिटल डेटाबेस तैयार किया जाएगा। इसमें सड़क की स्थिति, उसकी उम्र, क्षतिग्रस्त हिस्सों और मरम्मत की जरूरत से जुड़ी जानकारी दर्ज होगी।

इसके बाद नियमित अंतराल पर सड़कों का मूल्यांकन किया जाएगा। इससे यह तय करना आसान होगा कि किस सड़क को पहले मरम्मत की जरूरत है और कहां संसाधनों का बेहतर उपयोग किया जा सकता है। सरकार का दावा है कि इससे सड़कों की गुणवत्ता में सुधार होगा और अनावश्यक खर्च भी कम होगा।

धूल-मुक्त दिल्ली का सपना

इस योजना का एक बड़ा लक्ष्य दिल्ली को धूल प्रदूषण से राहत दिलाना भी है। राजधानी की सड़कों के किनारे वैज्ञानिक तरीके से ग्रीन बेल्ट विकसित की जाएगी। स्थानीय जलवायु के अनुकूल पौधों और पेड़ों को प्राथमिकता दी जाएगी ताकि पर्यावरणीय संतुलन भी बना रहे।

इसके साथ ही टिकाऊ लैंडस्केपिंग, हरित अवसंरचना और पर्यावरण-अनुकूल डिजाइन को बढ़ावा दिया जाएगा।

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने फिलिपींस के मिंदनाओ में भूकंप से हुई जानमाल की क्षति पर दुख व्यक्त किया

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने फिलिपींस के मिंदनाओ में आज भूकंप से हुई जानमाल की क्षति पर दुख व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने इस हादसे

के मृतकों के परिवारजनों के प्रति हार्दिक संवेदना प्रकट करने के साथ ही घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की। श्री मोदी ने कहा कि फिलिपींस की अवाम और सरकार के साथ भारत एकजुटता से खड़ा है। प्रधानमंत्री ने एक्स पर लिखाः "फिलिपींस के मिंदनाओ में आज भूकंप से हुई जानमाल की क्षति से मुझे दुख पहुंचा है। मैं मृतकों के परिवारजनों के प्रति हार्दिक संवेदना प्रकट करते हुए घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूं। फिलिपींस की अवाम और जनता के साथ भारत एकजुटता से खड़ा है।"

प्रधानमंत्री मोदी तिरुचिरापल्ली से दो अमृत भारत एक्सप्रेस और एक यात्री ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे

(जीएनएस)।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली से दो अमृत भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ियों और एक यात्री रेलगाडी को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इनमें से एक यात्री रेलगा ड़ी केरल के एनार्कुलम से रवाना होगी। रेल मंत्रालय ने कहा कि इन नई रेल सेवाओं से तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा और झारखंड के यात्रियों को लाभ होगा।

मंत्रालय ने बताया कि पोदानूर-धनबाद अमृत भारत एक्सप्रेस कोयंबटूर के औद्योगिक क्षेत्र को पूर्वी

भारत के कोयला और खनिज उत्पादक क्षेत्र झारखंड से सीधे जोड़ेगी। नागरकोइल-चारलापल्ली अमृत भारत एक्सप्रेस तेलंगाना के लिए इस क्षेत्र की पहली सीधी अमृत भारत सेवा है, जो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीस से अधिक जिलों से होकर गुजरेगी। वहीं, रामेश्वरम-मंगलुरु और तिरुनेलवेली-मंगलुरु एक्सप्रेस ट्रेनें तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक के तीर्थयात्रियों और तटीय यात्रियों के लिए सीधे मार्ग उपलब्ध कराएंगी।

इस अवसर पर केरल के शोरानूर, कुट्टीपुरम और चांगनास्सेरी में तीन अमृत भारत स्टेशनों का भी उद्घाटन किया जाएगा।

प्रधानमंत्री ने धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा को उनके शहादत दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित की

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा जी को उनकी शहादत के दिन श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने जल,

जंगल और जमीन की रक्षा के लिए विदेशी शासन के विरुद्ध अदम्य साहस से संघर्ष किया।

श्री मोदी ने कहा कि उनका पूरा जीवन आदिवासी समुदाय के आत्मसम्मान, संस्कृति और अधिकारों की रक्षा के लिए समर्पित था। प्रधानमंत्री ने कहा कि मातृभूमि के लिए उनके बलिदान की गाथा देश की हर पीढ़ी में देशभक्ति की भावना को प्रेरित करती रहेगी।

ईडी की रेड करा पंजाब के हिन्दू व्यापारियों को तंग कर रही ईडी पार्टी, भड़के केजरीवाल

(जीएनएस)।

पंजाब के हिन्दू व्यापारियों के यहां मंगलवार को एक बार फिर ईडी की रेड पड़ने पर आम आदमी पार्टी और उसकी पंजाब सरकार ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। पंजाब सरकार ने व्यापारियों को पंजाब के विकास की रीढ़ की हड्डी बताते हुए उनके साथ खड़े होने की बात कही है। उधर, "आप" के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने केंद्र की सत्ता में बैठी भाजपा पर तीखा हमला बोला है।

उन्होंने कहा कि ईडी पार्टी पंजाब के हिन्दू व्यापारियों पर ईडी की रेड कराकर उन्हें तंग कर रही है। उन्होंने सभी व्यापारियों से अपील करते हुए कहा कि कोई भी व्यापारी घबराए नहीं, पूरा पंजाब आपके साथ खड़ा है। हम सब मिलकर ईडी पार्टी का मुकाबला करेंगे।

अरविंद केजरीवाल ने एक्स पर कहा कि ईडी पार्टी मंगलवार को एक बार फिर पंजाब के हिंदू व्यापारियों पर ईडी की रेड कर रही है। ईडी पार्टी पंजाब के छोटे-छोटे हिंदू व्यापारियों को तंग कर रही है। मेरी सभी व्यापारियों से अपील है कि घबराने की कोई बात नहीं है, पूरा पंजाब और पंजाब सरकार आपके साथ है। हम सब मिलकर ईडी पार्टी का मुकाबला करेंगे।

अरविंद केजरीवाल ने अकाली दल और भाजपा के बीच गठबंधन को लेकर चल रही चर्चा पर कहा कि सुना है कि ईडी पार्टी पंजाब की बेअदबी पार्टी/चिट्टा पार्टी से गठबन्धन करने को बहुत बेचैन है, पर बेअदबी पार्टी/चिट्टा पार्टी उनको घास नहीं डाल रही है।

उधर, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने ईडी की रेड पर कहा कि पंजाब के हिंदू व्यापारी हमारे राज्य के आर्थिक विकास की रीढ़ की हड्डी हैं और 'रंगला पंजाब' बनाने में उनका बहुत बड़ा योगदान है।

टीएमसी में 'हस्ताक्षर कांड'! ममता-अभिषेक के ठिकानों पर सीआईडी की रेड, भड़के कल्याण ने साधा सीएम पर निशाना

(जीएनएस)।

पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस का सियासी संकट मंगलवार को और गहरा गया, जब उकऊ ने पूर्व उट ममता बनर्जी और राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी से जुड़े कई ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की। यह कार्रवाई विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष

की नियुक्ति से जुड़े कथित फर्जी हस्ताक्षर मामले की जांच के तहत की

गई। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक दोपहर करीब 12 बजे उकऊ की एक टीम कोलकाता स्थित टीएमसी के केंद्रीय कार्यालय 30इ हरिश चटर्जी स्ट्रीट पहुंची। टीम के साथ कालीघाट थाने की पुलिस और बड़ी संख्या में महिला पुलिसकर्मी भी मौजूद थीं।

जांच एजेंसी की तीन अलग-अलग टीमों ने एक साथ कार्रवाई की। एक टीम ममता बनर्जी के आवास पहुंची, जबकि दूसरी टीम अभिषेक बनर्जी के कार्यालय और तीसरी टीम उनके आवास पर तलाशी लेने पहुंची, आपको बता दें कि इन दिनों ममता बनर्जी दिल्ली दौरे पर हैं, उकऊ अधिकारियों के मुताबिक, हाल ही में अभिषेक बनर्जी को नोटिस भेजकर कथित फर्जी हस्ताक्षरों के संबंध में जानकारी मांगी गई थी। जवाब में उन्होंने बताया कि विधायकों के हस्ताक्षर पार्टी के केंद्रीय कार्यालय में एकत्र किए गए थे। इसी जानकारी के आधार पर जांच एजेंसी ने संबंधित स्थानों की तलाशी ली है।

क्या है 'हस्ताक्षर कांड'?

विवाद की शुरूआत 27 मई को हुई थी, जब टीएमसी विधायक फ्रछु१३ इंल्ली१ी और संदीपन साहा ने विधानसभा अध्यक्ष को शिकायत सौंपकर दावा किया कि 6 मई को हुई पार्टी बैठक में नेता प्रतिपक्ष के चयन को लेकर कोई प्रस्ताव पारित नहीं किया गया था।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी रक्षा अलंकरण समारोह 2026(चरण-1) में शामिल हुए

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी आज रक्षा अलंकरण समारोह 2026(चरण-1) में शामिल हुए, जहां हमारे वीर जवानों को वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने राष्ट्र के प्रति उनके अदम्य साहस, कर्तव्यनिष्ठा और निःस्वार्थ सेवा पर गर्व व्यक्त किया।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने एक्स पर लिखाः 'रक्षा अलंकरण समारोह 2026 (चरण-1) में शामिल हुआ, जहां हमारे वीर जवानों को वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हमें राष्ट्र के प्रति उनके अदम्य साहस, कर्तव्यनिष्ठा और निःस्वार्थ सेवा पर गर्व है।'

एनडीआरएफ की तर्ज पर यूपी में बनेगा स्पेशलाइज्ड रेस्क्यू ग्रुप, हर तहसील तक पहुंचेगी फायर सर्विस, जानें योगी सरकार का पूरा प्लान

(जीएनएस)।

लखनऊ, उत्तर प्रदेश में आपदा और दुर्घटनाओं से निपटने के लिए एनडीआरएफ की तर्ज पर स्पेशलाइज्ड रेस्क्यू ग्रुप (एसआरजी) बनाया जाएगा। 240 कर्मियों को विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हर तहसील तक फायर सर्विस पहुंचाने, हाईराइज भवनों के लिए आधुनिक अग्निसुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने और फायर सेवाओं के विस्तार के निर्देश दिए।

उत्तर प्रदेश में आपदा और विशेष आपात परिस्थितियों में राहत एवं बचाव कार्यों को और प्रभावी बनाने के लिए अग्निशमन एवं आपात सेवा विभाग में स्पेशलाइज्ड रेस्क्यू ग्रुप (एसआरजी) का गठन किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर पहले चरण में प्रदेश के 10 जिलों में एसआरजी की स्थापना की तैयारी पूरी कर ली गई है। इसके लिए 240 कर्मियों को राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ), सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ), भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी), केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) समेत अन्य विशेषज्ञ संस्थानों में उन्नत प्रशिक्षण दिया जाएगा।

सोमवार को अग्निशमन एवं आपात सेवा विभाग की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश तेजी से शहरी, औद्योगिक और आर्थिक विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा है। ऐसे में नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अग्निशमन एवं आपात सेवा व्यवस्था को समय की जरूरतों के अनुरूप और मजबूत बनाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि विभाग अब केवल आग बुझाने तक सीमित नहीं है, बल्कि लोगों के जीवन, संपत्ति, उद्योगों और निवेश की सुरक्षा का भी महत्वपूर्ण आधार बन चुका है। मुख्यमंत्री ने कहा कि एसआरजी भवन ध्वस्त होने, बाढ़, रासायनिक दुर्घटनाओं, ऊंचाई पर फंसे लोगों के रेस्क्यू और संकरे स्थानों में बचाव

जैसे जटिल अभियानों में आधुनिक उपकरणों और विशेष प्रशिक्षण के साथ त्वरित कार्रवाई करने में सक्षम होगी।

296 तहसीलों में संचालित हैं 326 अग्निशमन केंद्र

बैठक में डीजी फायर सर्विस ने मुख्यमंत्री को बताया कि प्रदेश की 350 तहसीलों में से 296 तहसीलों में 326 स्थायी अग्निशमन केंद्र संचालित हैं। 26 नए केंद्र लोकार्पण के लिए तैयार हैं, जबकि 25 केंद्रों का निर्माण कार्य जारी है। इसके अलावा 47 नए केंद्रों की डीपीआर तैयार की जा रही है। मुख्यमंत्री ने शेष तहसीलों में भी अग्निशमन सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए।

हाईराइज भवनों के लिए खरीदे जाएंगे आधुनिक उपकरण

मुख्यमंत्री ने कहा कि नोएडा, गाजियाबाद, लखनऊ, कानपुर, वाराणसी और प्रयागराज जैसे शहरों में तेजी से बढ़ रही बहुमंजिला इमारतों ने अग्निसुरक्षा की नई चुनौतियां पैदा की हैं। इनसे निपटने के लिए आधुनिक संसाधनों और विशेष व्यवस्थाओं की जरूरत है। अधिकारियों ने बताया कि वर्ष 2026-27 में 102 मीटर क्षमता के 10, 90 मीटर क्षमता के तीन और 72 मीटर क्षमता के सात हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म खरीदने की योजना है। इसके अलावा 100 मंजिल तक प्रभावी अग्निशमन क्षमता वाले आधुनिक तकनीक से लैस 14 विशेष फायर फाइटिंग वाहनों की खरीद भी प्रस्तावित है।

नौ वर्षों में दोगुनी से अधिक बढ़ी विभाग की क्षमता

बैठक में बताया गया कि वर्ष 2017 के बाद से अग्निशमन एवं आपात सेवा विभाग की क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। प्रदेश में अग्निशमन केंद्रों की संख्या 140 से बढ़कर 260 हो गई है तथा 114 नए केंद्र स्थापित किए गए हैं। इसी अवधि में फायर वाहनों की संख्या 750 से बढ़कर 1660 हो गई है, जबकि 400 अतिरिक्त वाहनों की खरीद प्रक्रिया जारी है। डायल-112 के साथ एकीकरण, ऑनलाइन सेवाओं के विस्तार और नई भर्तियों से विभाग की कार्यक्षमता में भी सुधार हुआ है।

फायर ऑडिट और जनजागरूकता पर जोर

मुख्यमंत्री ने फसलों में आग लगने की घटनाओं को रोकने के लिए जनजागरूकता और सामुदायिक भागीदारी को मजबूत बनाने पर बल दिया। अधिकारियों के अनुसार वर्ष 2025-26 के दौरान प्रदेशभर में 1.20 लाख से अधिक फायर ऑडिट किए गए। इसके अलावा 31 हजार से अधिक मॉक ड्रिल, 75 हजार से अधिक प्रशिक्षण कार्यक्रम और 16.55 लाख लोगों तक पहुंचने वाले जनजागरूकता अभियान चलाए गए। मुख्यमंत्री ने अस्पतालों, होटलों, स्कूलों, औद्योगिक प्रतिष्ठानों और बहुमंजिला भवनों में नियमित फायर ऑडिट कराने तथा सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

फायर एनओसी प्रक्रिया हुई और आसान

निवेश और उद्योगों की जरूरतों को देखते हुए मुख्यमंत्री ने फायर एनओसी व्यवस्था को और अधिक सरल, पारदर्शी तथा समयबद्ध बनाने के निर्देश दिए। अधिकारियों ने बताया कि फायर सर्विस पोर्टल को निवेश मित्र 3.0 से एकीकृत किया जा चुका है। एनओसी की वैधता अवधि तीन वर्ष से बढ़ाकर पांच वर्ष कर दी गई है। 1 जनवरी से 31 मई 2026 के बीच प्राप्त 14,717 ऑनलाइन आवेदनों में से 10,670 मामलों में एनओसी जारी की गई है।

सभी ब्लॉकों में तैयार किए गए अग्निमित्र

बैठक में बताया गया कि प्रदेश के सभी ब्लॉकों में अग्निमित्र और अग्निसचेतक तैयार करने का लक्ष्य पूरा कर लिया गया है। वर्ष 2026 में लगभग 44 हजार स्वयंसेवकों को रिफ्रेशर प्रशिक्षण दिया गया है। आगामी चरण में इनके लिए समर्पित वेब पोर्टल और मोबाइल एप विकसित किया जाएगा। साथ ही सिविल डिफेंस, होमगार्ड और पीआरडी जैसी इकाइयों को भी इस अभियान से जोड़ा जाएगा।

जो भारत की संस्कृति, विरासत और मूल्यों का सम्मान करेगा वही यहां सम्मानपूर्वक रह सकेगा: सीएम योगी

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि भारत की धरती कोई धर्मशाला नहीं है। जो भारत की संस्कृति, विरासत और मूल्यों का सम्मान करेगा, वही ...और पढ़ें

(जीएनएस)।

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि भारत की पहचान उसकी सांस्कृतिक विरासत और जीवन मूल्यों से है। इसलिए जो लोग इनका सम्मान करते हैं, वही इस देश की आत्मा से जुड़ सकते हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा, भारत की धरती कोई धर्मशाला नहीं है। जो भारत की संस्कृति, विरासत और मूल्यों का सम्मान करेगा, वही यहां सम्मानपूर्वक रह सकेगा। जो भारत की आत्मा और उसके संस्कारों को स्वीकार नहीं कर सकता, उसके लिए यहां कोई स्थान नहीं है।

सीतापुर रोड स्थित ब्रज की रसोई परिसर में आयोजित श्रीराम कथा के समापन समारोह में भारतीय संस्कृति, सनातन परंपरा और राष्ट्रहित से जुड़े मुद्दों पर अपने विचार रखे।

रामभद्राचार्य के योगदान को बताया प्रेरणादायी

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने पद्म विभूषण जगदुरु रामानंदाचार्य स्वामी रामभद्राचार्य महाराज के योगदान की सराहना करते हुए कहा कि चित्रकूट

में देश के पहले दिव्यांग विश्वविद्यालय की स्थापना कर उन्होंने सेवा, समर्पण और सामाजिक उत्थान का अद्वितीय उदाहरण प्रस्तुत किया है। उन्होंने कहा कि इस आयु में भी रामभद्राचार्य महाराज विश्राम करने के बजाय देश-विदेश में श्रीराम कथा के माध्यम से लोकमंगल और राष्ट्रजागरण का कार्य कर रहे हैं।

'श्रीराम का नाम देश को जोड़ने वाला सूत्र'

सीएम योगी ने कहा कि श्रीराम जन्मभूमि आंदोलन किसी राजनीतिक दल, संगठन या व्यक्ति का आंदोलन नहीं था, बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था का प्रतीक था। उन्होंने कहा कि भगवान श्रीराम का नाम वह सूत्र रहा है, जिसने उत्तर से दक्षिण तक पूरे देश को सांस्कृतिक और भावनात्मक रूप से एकजुट रखने का कार्य किया।

उन्होंने कहा कि यदि व्यक्ति भगवान राम के आदर्शों का थोड़ा-सा अंश भी अपने जीवन में आत्मसात कर ले, तो न केवल उसका जीवन बेहतर बन सकता है, बल्कि समाज और राष्ट्र के कल्याण का मार्ग भी प्रशस्त हो सकता है।

कंस और मारीच के प्रसंगों से दिया संदेश

मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में पौराणिक प्रसंगों का उल्लेख करते हुए कहा कि इतिहास और धर्मग्रंथ हमें सज्जन शक्ति को संगठित करने तथा अधर्म और अन्याय के विरुद्ध खड़े होने की प्रेरणा देते हैं। उन्होंने कंस और मारीच के उदाहरण देते हुए कहा कि गलत संगति और स्वार्थपूर्ण सलाह हमेशा व्यक्ति, समाज और राष्ट्र के लिए हानिकारक साबित होती है।

यह भी पढ़ें- अखिलेश यादव का बड़ा दावा, प्रयागराज की सभी सीटों पर उम्मीदवार बदलने की भाजपा कर रही तैयारी, 2027 में 225 विधायकों के कटेंगे टिकट

'संत समाज हमेशा जोड़ने का काम करता है'

योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कुछ शक्तियां समाज को जाति, क्षेत्र, भाषा और अन्य आधारों पर विभाजित करने का प्रयास करती हैं, जबकि संत समाज सदैव लोगों को जोड़ने, सामाजिक समरसता बढ़ाने और राष्ट्र को मजबूत करने का कार्य करता है।

मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में उपस्थित श्रद्धालुओं का अभिनंदन करते हुए कहा कि प्रभु श्रीराम के आदर्श और संतों का सानिध्य व्यक्ति को जीवन की कठिन परिस्थितियों में भी सकारात्मक ऊर्जा और आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है।

यूपी में सभी 403 विधानसभा में बनेगी 80 करोड़ की लागत से सड़कें-पुलिया, 10 जून के बाद सीएम योगी शुरू करेंगे मंडलीय दौरे, हर दिन जाएंगे 2 मंडल

अब मुख्यमंत्री योगी 10 जून के बाद जब मंडलीय दौरे पर निकलेंगे तो वह दल के विधायकों और विधान परिषद सदस्यों के साथ बैठक कर विकास कार्यों की समीक्षा भी करेंगे. मुख्यमंत्री एक दिन में दो-दो मंडलों का दौरा करेंगे. यूपी में सभी 403 विधानसभा में बनेगी 80 करोड़ की लागत से सड़कें-पुलिया, 10 जून के बाद सीएम योगी शुरू करेंगे मंडलीय दौरे, हर दिन जाएंगे 2 मंडल 403 विधानसभा क्षेत्रों 80 से 85 करोड़ रुपए विकास करने के लिए जिलों की कार्ययोजना मंगा ली गई है. बजट न खर्च कर पाने के कारण वापस हो जाने वाली विभागीय धनराशि को लेकर विपक्ष की आलोचना से भी बचा जा सकेगा. मुख्यमंत्री योगी ने बहुत सोच-विचार कर गांवों में सड़क और पुलिया के निर्माण की योजना तैयार की है. (जीएनएस)।

लखनऊः उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव भले की अगले साल होने हैं, लेकिन सूबे की योगी सरकार पूरी तरीके से चुनावी मोड में आ गई. इसके चलते ही अब गांवों में अवस्थापना सुविधाओं के विकास पर सरकार से अपना ध्यान केन्द्रित करते हुए सूबे के 403 विधानसभा क्षेत्रों 80 से 85 करोड़ रुपए विकास करने के लिए जिलों की कार्ययोजना मंगा ली

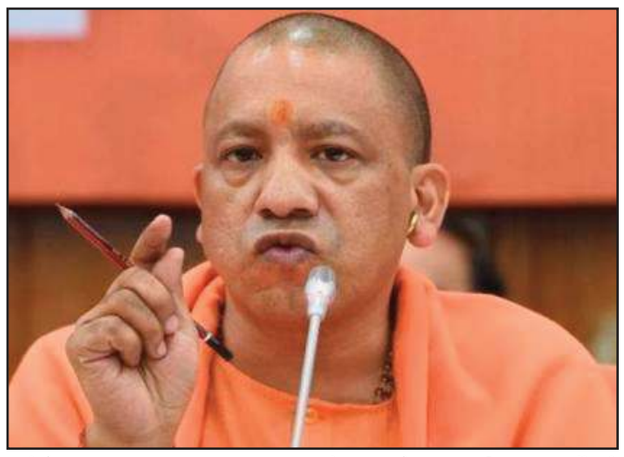

गई है.

बताया जा रहा है कि सरकार की मंशा हर विधानसभा क्षेत्र में सड़क और पुलिया के निर्माण में 80 से 85 करोड़ रुपए खर्च करने की है. ताकि विधानसभा चुनावों के पहले ग्रामीण क्षेत्रों में प्रदेश सरकार के कराए यह कार्य लोगों को दिखाई दे. इसके अलावा हर साल बजट न खर्च कर पाने के कारण वापस हो जाने वाली विभागीय धनराशि को लेकर विपक्ष की आलोचना से भी बचा जा सकेगा.

पुलिया और सड़क का निर्माण क्यों

इस सोच के चलते ही मुख्यमंत्री योगी ने बहुत सोच-विचार कर गांवों में सड़क और पुलिया के निर्माण की योजना तैयार की है. अब मुख्यमंत्री योगी 10 जून के बाद जब मंडलीय दौरे पर निकलेंगे तो वह दल के विधायकों और विधान परिषद सदस्यों के साथ बैठक कर विकास कार्यों की समीक्षा भी करेंगे. मुख्यमंत्री एक दिन में दो-दो मंडलों का दौरा करेंगे.

इस दौरान मुख्यमंत्री जनप्रतिनिधियों से उनके द्वारा प्रस्तावित किए गए कार्यों में से उनकी शीर्ष प्राथमिकताओं के बारे में जानकारी करेंगे. जनप्रतिनिधि जिस कार्य को अधिक महत्वपूर्ण बताएंगे वह काम सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर विभागों से कार्य करने का कहा जाएगा.

इसके साथ ही हर विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों में सड़क और पुलिया के निर्माण को लेकर मिले आवेदनों पर त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश लोक निर्माण विभाग (पीडबल्यूडी) के अफसरों को दिए जाएंगे. मुख्यमंत्री योगी का मानना है कि सड़क और पुलिया के निर्माण की मांग हर ग्रामीण करता है और इनका निर्माण होने के ग्रामीण खुश होते हैं, इस विधानसभा चुनाव के पहले हर विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों में यह कार्य जरूर करवाए जाएं.

पीडब्ल्यूडी के बजट से होगा निर्माण

वैसे भी सड़क और पुलिया के निर्माण के लिए पीडब्ल्यूडी के पास धन के कमी नहीं है.पीडब्ल्यूडी को इस वर्ष विकास कार्यों के लिए 35,156 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं. जिसमें से 11,718 करोड़ रुपए नए कार्यों के लिए है. शेष बजट पहले से चल रही योजनाओं पर खर्च किया जा रहा है.

विभागाध्यक्ष एके द्विवेदी के मुताबिक लगभग 35 हजार करोड़ रुपए से नई सड़कें व पुल-पुलियों के निर्माण कार्य इस वर्ष कराए जाएंगे. जिलों से मिली कार्ययोजना में से चिन्हित किए जाने वाले कार्यों को शुरू कराने के लिए टेंडर प्रक्रिया जल्द से जल्द शुरू कराई जाएगी, ताकि दिसंबर तक बजट का पूरा उपयोग किया जा सके.

इसी क्रम में ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क और पुलिया के निर्माण को सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर विभाग पूरा कराएगा. इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल मुहैया करने के लिए तालाब के निर्माण, तालाबों की सफाई और हैंडपंप आदि ठीक करने का कार्य भी जोर-शोर से किया जाएगा.

भीषण गर्मी में भी बिजली आपूर्ति में यूपी नंबर-1, सीएम योगी बोले- किसी भी हाल में बिजली आपूर्ति बाधित नहीं होनी चाहिए

(जीएनएस)।

लखनऊ, भीषण गर्मी में उत्तर प्रदेश बिजली आपूर्ति में देश का नंबर-1 राज्य बन गया है. 7 जून को 31,147 मेगावाट रिकॉर्ड डिमांड पूरी की गई. उट योगी के निर्देश पर बिजलीकर्मी दिन-रात सक्रिय हैं.

बिजली आपूर्ति में यूपी नंबर वन

प्रचंड गर्मी के बावजूद उत्तर प्रदेश बिजली आपूर्ति में देश का नंबर-1 राज्य बन गया है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सतर्क निर्देशन में यूपी पावर कारपोरेशन (यूपीपीसीएल) ने 7 जून को 31,147 मेगावाट की रिकॉर्ड डिमांड पूरी की, जो देश में सबसे अधिक है.

यूपीपीसीएल के निदेशक वितरण ज्ञानेंद्र धर द्विवेदी ने बताया कि 7 जून को प्रदेश में बिजली की मांग 31,147 मेगावाट पहुंच गई, जिसे पूरी तरह पूरा किया गया. 6 जून को 31,049 मेगावाट और 5 जून को 29,130 मेगावाट डिमांड पूरी की गई. 8 जून को दोपहर 12 बजे 27,838 मेगावाट बिजली आपूर्ति की गई.

मेरठ में मॉडल को शादी का झांसा देकर 10 साल शोषण, 3 बार अबॉर्शन और धर्मांतरण का बनाया दबाव

दिन-रात मैदान में डटे बिजलीकर्मी

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर बिजली विभाग की टीमें चौबीसों घंटे सक्रिय हैं. ट्रांसफार्मर, फीडर और उपकेंद्रों की निरंतर निगरानी की जा रही है. गर्मी के मौसम में अतिरिक्त लोड को देखते हुए मेंटेनेंस कार्य तेज कर दिए गए हैं. बिजलीकर्मी दिन-रात फील्ड में रहकर खराबियों को तुरंत दूर कर रहे हैं.

निगरानी और रखरखाव पर विशेष ध्यान

विभाग ने सभी स्तरों पर सतर्कता बढ़ा दी है. संभावित खराबियों को रोकने के लिए तेजी से मेंटेनेंस किया जा रहा है. शिकायतों के त्वरित निस्तारण के लिए भी विशेष व्यवस्था की गई है.

मुख्यमंत्री का सख्त निर्देश

सीएम योगी ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि गर्मी के इस मौसम में किसी भी हाल में बिजली आपूर्ति बाधित नहीं होनी चाहिए. यूपीपीसीएल की टीमें इस चुनौती को सफलतापूर्वक पूरा कर रही हैं.

अब CUET-UG कराएगा लखनऊ विश्वविद्यालय में बीफार्मा में प्रवेश, जल्द आएगा फॉर्म

(जीएनएस)।

लखनऊः लखनऊ विश्वविद्यालय के इंस्टिट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेज में संचालित बी.फार्म. पाठ्यक्रम में शैक्षणिक सत्र 2026-27 से प्रवेश प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है. अब तक बी.फार्म. में प्रवेश डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय (AKTU) द्वारा आयोजित काउंसलिंग प्रक्रिया के माध्यम से किया जाता था, जबकि इस वर्ष से लखनऊ विश्वविद्यालय स्वयं कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट (CUET-UG) के आधार पर प्रवेश प्रदान करेगा.

लखनऊ विश्वविद्यालय के कुल सचिव डॉ. भावना मिश्रा ने बताया कि इ.ढँ१. पाठ्यक्रम में प्रवेश के इच्छुक अभ्यर्थियों के लिए CUET-UG 2026 में सम्मिलित होना अनिवार्य होगा. CUET-UG का रिजल्ट घोषित होने के बाद अभ्यर्थी लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रवेश पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे. प्रवेश प्रक्रिया पूर्णतः उवएळ-वऋ में प्राप्त अंकों के आधार पर तैयार की गई मेरिट सूची के अनुसार संचालित की जाएगी.

बी.फार्म. पाठ्यक्रम की 60 सीटों में प्रवेश के लिए अभ्यर्थी का किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से बारवीं (10+2) परीक्षा PCB/ PCM/ PCMB (जिसमें अंग्रेजी एक विषय हो) में उत्तीर्ण होना आवश्यक है.

विश्वविद्यालय प्रशासन ने इच्छुक अभ्यर्थियों से अपील की है कि वे CUET-UG परिणाम घोषित होने के पश्चात निर्धारित समयावधि में ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया पूर्ण करें और प्रवेश संबंधी नवीनतम सूचनाओं के लिए लखनऊ विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट का नियमित अवलोकन करते रहें.

उल्लेखनीय है कि बी.फार्म. पाठ्यक्रम 4 साल की स्नातक डिग्री है, जो 8 सेमेस्टर में विभाजित है. साल 2021 से संचालित इस पाठ्यक्रम के 2 बैच सफलतापूर्वक उत्तीर्ण हो चुके हैं. वर्तमान में इसके पहले छात्र फार्मास्युटिकल उद्योग, उच्च शिक्षा एवं अनुसंधान के विभिन्न क्षेत्रों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं.

लखनऊः सिविल अस्पताल की इमरजेंसी में फायर सेफ्टी के काम के दौरान गिरी फॉल सीलिंग; बाल-बाल बचे 9 मरीज

(जीएनएस)।

लखनऊः लखनऊ के प्रतिष्ठित सिविल अस्पताल की इमरजेंसी में उस समय अचानक अफरा-तफरी मच गई जब फाइबर की फॉल सीलिंग का एक बड़ा हिस्सा भरभराकर गिर गया. यह हादसा उस वक्त हुआ जब इमरजेंसी वार्ड के अंदर फायर सेफ्टी से जुड़ा कुछ जरूरी काम चल रहा था.

गनीमत यह रही कि मलबे की सीधी चपेट में कोई मरीज या उनका तीमारदार नहीं आया, जिससे एक बड़ा हादसा होने से टल गया. लखनऊ सिविल अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉ. देवेश चंद्र पांडेय ने बताया कि मामले की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दे दिए गए हैं.

हादसे के वक्त वार्ड में भर्ती थे 9 मरीजः मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉ. देवेश चंद्र पांडेय ने कहा कि दोपहर के समय इमरजेंसी वार्ड में फायर सेफ्टी उपकरणों की नियमित जांच और मरम्मत का कार्य निर्माण एजेंसी करा रही थी. इसी मरम्मत कार्य के दौरान छत पर ऊपर लगी फाइबर की फॉल सीलिंग अचानक भरभराकर धड़ाम से नीचे आ गिरी. सीलिंग गिरने की तेज आवाज सुनते ही वार्ड में भर्ती मरीजों के तीमारदार और ड्यूटी पर तैनात अस्पताल स्टाफ बुरी तरह घबरा गए.

मरीजों को सुरक्षित वार्डों में किया गया शिफ्टः हादसे के वक्त इमरजेंसी वार्ड में कुल 9 गंभीर मरीज भर्ती थे, जिन्हें तुरंत सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया गया. स्थिति की गंभीरता और खतरे को देखते हुए इमरजेंसी वार्ड को डॉक्टरों के निर्देश पर तुरंत खाली करा लिया गया. इसके बाद सभी मरीजों को अस्पताल के अन्य सुरक्षित वार्डों में बेड अलॉट कर इलाज के लिए भेजा गया. मौके पर मौजूद एक प्रत्यक्षदर्शी रवि शंकर ओझा ने बताया कि फॉल सीलिंग गिरने से कुछ महंगे मेडिकल उपकरण और फर्नीचर भी क्षतिग्रस्त हुए हैं.

हादसे के बाद अस्पताल प्रशासन में हड़कंपः इस अचानक हुए हादसे के बाद अस्पताल प्रशासन के आला अधिकारियों में हड़कंप मच गया. आनन-फानन में पीडब्ल्यूडी की इंजीनियरिंग टीम को बुलाकर बाकी बची सीलिंग की तकनीकी जांच कराई गई. इसके साथ ही सुरक्षा के मद्देनजर पूरे इमरजेंसी क्षेत्र को मरीजों के लिए अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया.

उटर ने दिए जांच के आदेशः मरीजों के परिजनों ने आरोप लगाया कि सिविल अस्पताल में रखरखाव के नाम पर सिर्फ कागजी खानापूर्ति होती है. लखनऊ सिविल अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉ. देवेश चंद्र पांडेय ने बताया कि मामले की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दे दिए गए हैं. फायर सेफ्टी का काम कर रही कार्यदायी एजेंसी और अस्पताल के संबंधित अधिकारियों से इसको लेकर स्पष्टीकरण मांगा जाएगा. स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने भी स्थिति का जायजा लेकर इमरजेंसी वार्ड को जल्द सुरक्षित बनाकर यहां सेवाएं शुरू करने के निर्देश दिए हैं.

नगर आयुक्त ने नाला सफाई कार्यों का किया निरीक्षण, कहा- 'नालों की सफाई गंभीरता से की जाए'

(जीएनएस)।

लखनऊ : मंगलवार को लखनऊ नगर निगम आयुक्त गौरव कुमार ने अलग-अलग क्षेत्र में जाकर नाला सफाई का निरीक्षण किया और जरूरी निर्देश दिए. नगर आयुक्त गौरव कुमार ने जोन-3 क्षेत्र के विभिन्न नालों का निरीक्षण किया. इस दौरान उनके साथ चीफ इंजीनियर (सिविल) महेश वर्मा, अधिशासी अभियंता जोन-3 नजमी मुजफ्फर सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे. निरीक्षण की शुरूआत टेढ़ी पुलिया चौराहे से इंजीनियरिंग कॉलेज चौराहे के मध्य स्थित सर्विस रोड के किनारे चल रहे नाला सफाई कार्य से हुई. नगर आयुक्त ने बकेट मशीन द्वारा की जा रही सफाई व्यवस्था को देखा और कार्यों को निर्धारित मानकों के अनुसार पूरा करने के निर्देश दिए.

नगर आयुक्त ने छुइयापुरवा चौराहे से अलीशा नगर चौराहे तक स्थित नाले का निरीक्षण किया. उन्होंने नाले की सफाई को और प्रभावी बनाने के लिए पुनः सफाई अभियान चलाने के निर्देश दिए, ताकि जल निकासी व्यवस्था पूरी तरह सुचारु बनी रहे.

लखनऊ विश्वविद्यालय न्यू कैंपस के निकट रेलवे पुलिया से बिठौली चौराहे तक स्थित नाले का निरीक्षण करते हुए नगर आयुक्त ने कुछ स्थानों पर फ्लोटिंग मटेरियल (तैरने वाली सामग्री) पाए जाने पर उसे तत्काल हटाने तथा नाले की दोबारा सफाई कराने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि बारिश के दौरान जलभराव की समस्या न हो, इसके लिए सभी नालों की सफाई पूरी गंभीरता से की जाए.

अधिकारियों ने नाला सफाई कार्यों का किया निरीक्षण

"कवरिंग हटाकर अंदर तक अच्छी तरह सफाई सुनिश्चित की जाए" : नगर आयुक्त ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि नालों की कवरिंग हटाकर अंदर तक अच्छी तरह सफाई सुनिश्चित की जाए तथा सफाई के बाद कवरिंग को व्यवस्थित ढंग से पुनः लगाया जाए. उन्होंने नाला सफाई के दौरान निकलने वाली सिल्ट को समयबद्ध तरीके से हटाने और किसी भी स्थान पर उसे जमा न होने देने के निर्देश भी दिए.

"अभियंता कार्यों की निगरानी करें" : नगर आयुक्त ने कहा कि नाला सफाई कार्यों में लगे सभी कर्मियों को आवश्यक सेफ्टी गियर्स उपलब्ध कराए जाएं तथा अभियंता नियमित रूप से कार्यों की निगरानी करें, जिससे सफाई अभियान पूरी गुणवत्ता और सुरक्षा के साथ संचालित हो सके.

निरीक्षण के बाद विकास कार्यों की समीक्षा की : नाला सफाई कार्यों के निरीक्षण के बाद नगर आयुक्त ने कश्मीरी मोहल्ला स्कूल का भी निरीक्षण किया. इस दौरान उन्होंने विद्यालय में चल रहे नवीनीकरण एवं विकास कार्यों की समीक्षा की. चीफ इंजीनियर (सिविल) महेश वर्मा एवं पर्यावरण अभियंता संजीव प्रधान की उपस्थिति में नए क्लासरूम निर्माण कार्यों की प्रगति का जायजा लिया गया. नगर आयुक्त ने गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध तरीके से कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए.

PRGI No.: UPHIN/25/A1698 Published & Owned by RAGINI JIGNESHKUMAR VAGHELA and Printed By SUSHILA SHUKLA at Krishna Printiers, 271/31 Chakmaki Dugawa, Rajendranagar, Lucknow-226018, Uttar Pradesh.
and Published from 538 GHA/85 Pataurganj, Near Janki Prasad Dharmshala, Sitapur Road, Niralanagar, Lucknow-226020, Uttar Pradesh. Editor : VINOD KUMARI
Regd.Office : B/13, Sneh Plaza Shopping Center, I.O.C. Road, Chandkheda, Ahmedabad - 382 424 Gujarat,India. Phone : (o) 7698333307 (M) 8485951747,7096333307
Email:navsarjansanskruti2016@gmail.com*navsarjansanskruti2016@yahoo.com*Website : www.navsarjansanskruti.com

सम्पादकीय

जनसंख्या का प्रश्न अब केवल जन्मदर का प्रश्न नहीं बल्कि जीवन की गुणवत्ता और संसाधनों की उपलब्धता का प्रश्न

आज भारत के सामने चुनौती जनसंख्या बढ़ाने या घटाने की नहीं है, बल्कि ऐसी व्यवस्था निर्मित करने की है जिसमें नागरिक आने वाले कल से भयभीत न हों। क्योंकि जहां भविष्य पर विश्वास होता है, वहां बच्चे बोझ नहीं, आशा बनकर जन्म लेते हैं और जहां भविष्य ही असुरक्षित हो, वहां घटती जन्मदर आंकड़ा नहीं, व्यवस्था पर लिखा हुआ एक मौन अभियोग बन जाता है।

रोटी, कपड़ा और मकान मनुष्य की प्राथमिक आवश्यकता है। रोटी के लिए रोजगार चाहिए, रोजगार के लिए शिक्षा चाहिए और शिक्षा के लिए धन चाहिए। कपड़े सस्ते भी पहने जा सकते हैं, लेकिन मकान सस्ता नहीं मिलता। यही वह कठोर यथार्थ है जिसके बीच आज का भारतीय परिवार अपने भविष्य का गणित बैठा रहा है। इसलिए भारत में जनसंख्या का प्रश्न अब केवल जन्मदर का प्रश्न नहीं रह गया है, बल्कि जीवन की गुणवत्ता और संसाधनों की उपलब्धता का प्रश्न बन चुका है।

भारत की जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग 17.7 प्रतिशत है, जबकि पृथ्वी के कुल भूभाग का मात्र 2.4 प्रतिशत हिस्सा ही भारत के पास है। यह असंतुलन अपने आप में बहुत कुछ कह देता है। भूमि सीमित है, जल सीमित है, संसाधन सीमित हैं, किंतु उन पर निर्भर लोगों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। आज भले ही कुल प्रजनन दर प्रतिस्थापन स्तर से नीचे पहुँच चुकी हो और जनसंख्या वृद्धि की गति मंद पड़ रही हो, किंतु वास्तविक जनसंख्या अभी भी बढ़ रही है। अर्थात प्रतिशत घट रहा है, पर संख्या बढ़ रही है। यही भारत की जनसांख्यिकीय विडम्बना है।

संसाधनों पर बढ़ता दबाव जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में दिखाई देता है। महानगरों में लाखों लोग एक कमरे के मकानों में जीवन बिताने को विवश हैं। जमीन के दाम सामान्य नागरिक की पहुँच से बाहर हो चुके हैं। एक मध्यमवर्गीय परिवार अपने जीवन की आधी से अधिक कमाई केवल एक छोटे से घर के लिए खर्च कर देता है। घर खरीदना आज आवश्यकता से अधिक एक संघर्ष बन चुका है। युवा नौकरी मिलने के बाद विवाह की नहीं, पहले मकान की चिंता करता है। उसके बाद बच्चों की शिक्षा का प्रश्न सामने खड़ा हो जाता है। आज शिक्षा भी एक महँगा निवेश बन चुकी है। अभिभावक जानते हैं कि केवल बच्चे को जन्म देना पर्याप्त नहीं है। उसे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देनी होगी, प्रतिस्पर्धा परीक्षाओं की तैयारी करानी होगी, तकनीकी कौशल उपलब्ध कराना होगा और फिर रोजगार की अनिश्चित दुनिया में उसे स्थापित करना होगा। ऐसे में समझदार और शिक्षित परिवार बच्चों की संख्या नहीं, उनकी गुणवत्ता पर ध्यान दे रहे हैं। यह केवल व्यक्तिगत निर्णय नहीं, बल्कि आर्थिक विवशता का परिणाम है। रोजगार की स्थिति भी जनसंख्या विमर्श को प्रभावित कर रही है। स्थायी नौकरियों का स्थान संविदा आधारित नियुक्तियों ने ले लिया है। लाखों युवा आधे वेतन में दोगुना काम कर रहे हैं। उनके सिर पर हर वर्ष अनुबंध नवीनीकरण की तलवार लटकती रहती है। भविष्य अनिश्चित है, पेंशन का भरोसा नहीं है और सामाजिक सुरक्षा का ढाँचा कमजोर है। जो व्यक्ति स्वयं अपने भविष्य को लेकर आश्वस्त नहीं है, वह कई बच्चों के भविष्य की जिम्मेदारी उठाने का साहस कैसे करेगा? यह स्थिति केवल युवाओं तक सीमित नहीं है। भारत तेजी से वृद्ध समाज की ओर भी बढ़ रहा है।

वरिष्ठ नागरिकों की संख्या लगातार बढ़ रही है, किंतु उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप व्यवस्थाएँ विकसित नहीं हो पा रही हैं। मेट्रो में बैठने की कुछ आरक्षित सीटें उनकी बढ़ती संख्या के सामने अपर्याप्त हैं। रेलों में आकस्मिक यात्रा करने वाले बुजुर्गों को आरामदायक बर्थ मिलना कठिन हो जाता है। कोविड काल के बाद रेलवे किराये में मिलने वाली रियायतें भी समाप्त हो गईं। स्वास्थ्य सुविधाएँ महँगी होती जा रही हैं और वृद्धावस्था की चुनौतियाँ बढ़ती जा रही हैं। प्रश्न यह भी है कि आने वाले वर्षों में इन बुजुर्गों की देखभाल कौन करेगा? वह युवा, जो स्वयं अस्थायी रोजगार, महँगी शिक्षा, बढ़ते किराये और सीमित आय के बीच संघर्ष कर रहा है? संयुक्त परिवारों का विघटन हो चुका है। सामाजिक सुरक्षा का भार परिवारों पर है और परिवार स्वयं आर्थिक दबावों से जूझ रहे हैं।

लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम (विनिमय) का उद्घाटन

(जीएनएस)।

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम (विनिमय) का उद्घाटन किया। इस अवसर पर केन्द्रीय गृह सचिव, आसूचना ब्यूरो के निदेशक, सीमा प्रबंधन सचिव और लैंड पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केन्द्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने कहा कि 2014 के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में लैंड पोर्ट अथॉरिटी को नई दिशा मिली। सुरक्षा-केंद्रित सोच से आगे बढ़कर लैंड पोर्ट को सुरक्षा के पहले कवच, व्यापार सुगमता के माध्यम और लोगों के बीच संपर्क सेतु के रूप में विकसित किया गया। साथ ही, सीमावर्ती क्षेत्रों के समग्र विकास, वैध व्यापार को बढ़ावा देने और सीमांत गांवों और जिलों में पलायन जैसी चुनौतियों से निपटने में भी लैंड पोर्ट ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। दोनों ओर के देशों की जनता के बीच सरल आवागमन के कारण परस्पर विश्वास बढ़ा है और संस्कृति का आदान-प्रदान भी बेहतर हुआ है। उन्होंने कहा कि भारत जैसे विशाल भू-सीमा वाले देश में सीमा प्रबंधन की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है।

श्री अमित शाह ने कहा कि गृह मंत्रालय स्मार्ट बॉर्डर की संकल्पना के साथ भारत की सीमाओं को सुरक्षित करने हेतु चतुष्कोणीय रणनीति पर कार्य कर रहा है। इस स्मार्ट बॉर्डर विजन में लैंड पोर्ट अथॉरिटी की महत्वपूर्ण भूमिका होने वाली है। उन्होंने कहा कि लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम (LPMS) में सभी हितधारकों की आवश्यकताओं तथा सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा गया है। यह व्यवस्था स्मार्ट बॉर्डर की संकल्पना के साथ मिलकर एक अभेद्य और सुरक्षित बॉर्डर का निर्माण करेंगे। उन्होंने कहा कि LPMS और स्मार्ट बॉर्डर मिलकर अधिक सुरक्षित और आधुनिक सीमा तंत्र बनाएंगे। उन्होंने कहा कि इससे अवैध गतिविधियों पर रोक और सुरक्षित व्यवस्था का निर्माण निश्चित है।

केन्द्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने कहा कि लैंड पोर्ट अथॉरिटी ने अपने लैंड पोर्ट्स के लिए एक आधुनिक, डिजिटल, एकीकृत और रियल-टाइम प्रबंधन प्रणाली विकसित कर सभी को एक साथ जोड़ने का काम किया है। उन्होंने कहा कि लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम के माध्यम से लैंड पोर्ट की मूल संकल्पना को लैंड पोर्ट अथॉरिटी ने पूरा कर दिया है। आगामी दिनों में हम लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम को देश की स्मार्ट सुरक्षा ग्रिड का एक महत्वपूर्ण अंग बनाएंगे, जिससे हमारी आर्थिक सुरक्षा के साथ-साथ भौतिक सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी। उन्होंने कहा कि लैंड पोर्ट अथॉरिटी की यह पहल स्मार्ट बॉर्डर की संकल्पना को पूर्ण रूप देने में सहायक सिद्ध होगा। यह प्रणाली कार्गो, पैसेंजर और वाहनों के प्रबंधन के लिए एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराएगी। इससे विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय बढ़ेगा और सूचना का आदान-प्रदान अत्यंत सरल हो जाएगा। 90% कागजी कार्यवाही समाप्त होगी। सिंगल इलेक्ट्रॉनिक विंडो तथा ऑटोमेटिक नंबर प्लेट पहचान आधारित गेट संचालन प्रणाली से काफी समय की बचत होगी। ट्रकों की प्रतीक्षा समय में लगभग 40% से 60% की कमी आएगी तथा गेट प्रोसेसिंग समय में 22% से 35% की कमी होगी। इससे न केवल व्यापार बढ़ेगा, बल्कि पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा और दोनों देशों के नागरिकों के बीच समन्वय, संवाद तथा सांस्कृतिक आदान-प्रदान भी बेहतर तरीके से हो सकेगा।

गृह मंत्री ने कहा कि छढटर के माध्यम से कुएक्रअळए, मोटर वाहन प्रणाली, उइकउ, इरऋ उऋख्रळ, वकऊअक और वछक्ढ एक मंच पर रियल-टाइम डेटा साझा होने से सीमा पर एजेंसियों के बीच समन्वय और मजबूत होगा। उन्होंने कहा कि इन सभी के बीच समन्वय और सूचना आदान-प्रदान का प्लेटफॉर्म देश के लिए बेहद सुविधाजनक सिद्ध होगा तथा विकास को नई गति प्रदान करेगा। उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों में लैंड पोर्ट्स में भी व्यापक बदलाव आया है। वर्ष 2014 में जहाँ

लैंड पोर्ट्स के माध्यम से 5,000 करोड़ रुपए का व्यापार होता था, वह आज बढ़कर 83,000 करोड़ रुपए हो गया है, यानि इसमें 16 गुना वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में 15 लैंड पोर्ट कार्यरत हैं और आने वाले 3 वर्षों में 11 अतिरिक्त लैंड पोर्ट भी संचालन में आ जाएंगे।

श्री अमित शाह ने विश्वास जताया कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने लैंड पोर्ट्स को लेकर जो संकल्पना रखी है, उसे हम समयबद्ध तरीके से अवश्य प्राप्त करेंगे। उन्होंने कहा कि लैंड पोर्ट अथॉरिटी की यह पहल जब स्मार्ट बॉर्डर की संकल्पना से जुड़ेगी, तो लैंड पोर्ट अथॉरिटी हमारी आर्थिक सुरक्षा और सीमा सुरक्षा दोनों का एक महत्वपूर्ण अंग बन जाएगी।

केन्द्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने कहा कि 9 जून 2026 देश के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण दिन के तौर पर गिना जाएगा। उन्होंने कहा कि यह प्रधानमंत्री के तौर पर श्री नरेन्द्र मोदी जी के सतत शासन के 12 साल पूरे होने का अवसर है। उन्होंने कहा कि कुछ नेता सत्ता में टिके रहने में ही ज्यादातर समय बिता देते हैं, लेकिन मोदी जी ने बीते 12 साल की सत्ता को साधना के रूप में स्वीकार करते हुए संपूर्ण देश को विकास की दिशा में आगे बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि मोदी जी ने देश सेवा को ही जीवन का अर्थ बनाकर देश को आगे ले जाने का संकल्प ले रखा है। निष्काम कर्मयोगी की तरह मोदी जी ने ऐसी अनेक उपलब्धियाँ हासिल की हैं, जिनके कारण आज भारत हर क्षेत्र में विश्व स्तर पर मील का पत्थर बनकर उभरा है।

श्री अमित शाह ने कहा कि मोदी जी चुने हुए प्रधानमंत्री के रूप में लगातार 4398 दिन का कार्यकाल आज पूरा करेंगे और कल श्री जवाहरलाल नेहरू जी का रिकॉर्ड तोड़ देंगे। उन्होंने कहा कि अब देश में चुने हुए प्रधानमंत्री के रूप में लगातार सबसे अधिक समय तक देश की सेवा करने का सौभाग्य प्रधानमंत्री मोदी जी को मिलेगा। उन्होंने कहा कि मोदी जी ने अपने कार्यकाल में जन कल्याण को शासन का सूत्र बनाया।

केन्द्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने एक नया विचार रखा कि भारत का हर नागरिक ऐसा हो, जिसके पास अपना पक्का घर हो। देखते-देखते आज 4 करोड़ पक्के घर भारत के नागरिकों को मिल चुके हैं और 2 करोड़ घरों का निर्माण होने वाला है। उन्होंने कहा कि दो साल बाद भारत में एक भी परिवार ऐसा नहीं रहेगा जिसके पास अपना पक्का घर न हो। घर के साथ गैस सिलिंडर, शौचालय, शुद्ध पेय जल, 5 लाख रुपए तक का मुफ़्त इलाज, प्रतिमाह प्रति व्यक्ति 5 से 7 किलो मुफ़्त अनाज जैसी सुविधाएं सुनिश्चित की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि चार-चार पीढ़ियों से बुनियादी सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रहे लोगों को मोदी जी ने अपने कार्यकाल के मात्र 12 वर्षों में यह बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई। श्री शाह ने कहा कि मोदी जी ने विकास के मायने बदल दिए। मोदी जी ने भारत के प्रशासनिक इतिहास में हर आयाम को छूने वाले '360 डिग्री विकास' की परिकल्पना शुरू की। भारत को पहले 'फ्रेजाइल फाइव' में गिना जाता था, जबकि मोदी जी के इन प्रयासों के कारण आज भारत सभी बड़े देशों में सबसे तेज गति से बढ़ती अर्थव्यवस्था भी बन गया है। गृह मंत्री ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठे हैं। अस्थिर वैश्विक परिस्थितियों के बावजूद भारत स्थिरता और तेज गति के साथ अपने लक्ष्यों की ओर आगे बढ़ रहा है।

श्री अमित शाह ने कहा कि बीते 12 वर्षों में भारत के लोकतंत्र में आमूलचूल बदलाव हुए हैं। उन्होंने कहा कि हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था में परिवारवाद, जातिवाद और भ्रष्टाचार ऐसे नासूर बन गए थे कि लोग इनके साथ जीने की आदत डाल चुके थे। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक मूलभूत परिवर्तन किया। उन्होंने परिवार की राजनीति, जाति की राजनीति और भ्रष्टाचार से कमाए धन के प्रभाव वाली राजनीति की जगह परफॉर्मेंस की राजनीति को स्थापित किया। इसके परिणामस्वरूप अनेक राज्यों में बार-बार चुनी जाने वाली सरकारें आईं, स्थिरता आई, स्थायी नीतियाँ बनीं और नीतियों का क्रियान्वयन तथा मॉनिटरिंग सरल हो गया। इस देश के राजनीतिक इतिहास में अगर किसी को पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस करने का श्रेय दिया जाए, तो वह श्रेय मोदी जी को जाता है। गृह मंत्री ने कहा कि महिला विकास की बात करने की जगह मोदी जी महिलाओं के नेतृत्व में विकास की दिशा में आगे बढ़े। सेना, पुलिस, विज्ञान, अनुसंधान, उद्यमिता, ड्रोन, खेल, स्टार्टअप, अंतरिक्ष - हर क्षेत्र में पहले इस देश की बेटियों को आगे बढ़ाने में समाज में झिझक थी। उन्होंने कहा कि आज कठिन से कठिन बॉर्डर इलाकों में तैनात बीएसएफ की सीमा प्रहरियों में बेटियाँ बराबर की संख्या में दिखती हैं, तो मन गद्गद हो जाता है। उन्होंने कहा कि मोदी जी ने नागरिकों से संवाद की संकल्पना को भी बदला। आकांक्षी जिलों और ब्लॉकों की रचना कर उन्होंने समावेशी विकास की परिकल्पना को जमीन पर उतारा। विकास की दौड़ में पीछे रह गए जिलों को 30 से अधिक पैरामीटर्स पर विकास का लक्ष्य और पर्याप्त संसाधन देकर उन्हें देश के सबसे विकसित जिलों के बराबर लाने का लक्ष्य रखा। उन्होंने कहा कि कुछ आकांक्षी जिले अब कई पैरामीटर्स में देश के टॉप पाँच जिलों के बराबर पहुँच चुके हैं। उन्होंने कहा कि समावेशी विकास की यह कल्पना अब प्रशासनिक प्रेरणा, लोगों की आकांक्षाओं को जगाने और पुरुषार्थ से जुड़कर आगे बढ़ रही है, जबकि पहले यह माना जाता कि था कि जो जिस जिले से मंत्री या सांसद बनेगा, वही अपने जिले का विकास करेगा।

केन्द्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने कहा कि बीते 12 वर्ष में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं। 81 करोड़ लोगों को हर महीने 5 किलो मुफ्त राशन मिल रहा है। 58 करोड़ नए जनधन बैंक खाते खुले हैं। 44 करोड़ से अधिक लोगों के पास 5 लाख रुपए तक के इलाज के लिए आयुष्मान भारत कार्ड हैं। 16 करोड़ घरों में नल से जल पहुँचा है। 13 करोड़ किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि के तहत सहायता मिली है। 12 करोड़ 76 लाख घरों में शौचालय बने हैं। 10 करोड़ 55 लाख घरों में गैस कनेक्शन पहुँचा है। 4 करोड़ से अधिक लोगों को पक्का आवास मिला है। 3 करोड़ से अधिक ग्रामीण गरीब महिलाएँ लखपति दीदी बन चुकी हैं और 93 लाख स्व-सहायता समूह बनाए गए हैं। आज भारत डिजिटल लेन-देन में दुनिया में नंबर एक, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में नंबर दो और स्टार्टअप इकोसिस्टम में नंबर तीन पर है। उन्होंने कहा कि चाहे कोविड की महामारी हो या वैश्विक युद्धों के कारण उत्पन्न आर्थिक संकट, हमने भारत को संभाला और आगे बढ़ाया। लगातार 12 वर्ष के जीडीपी के आँकड़े साक्षी हैं कि कठिनाइयाँ आईं, लेकिन दूरदर्शी और मजबूत नेतृत्व के जरिए हमने चुनौतियों का सामना किया। भारत के कोविड प्रबंधन को विकसित देशों ने भी दुनिया में आई महामारियों से निपटने के इतिहास में एक रिकॉर्ड के रूप में स्वीकारा है।

ऋतुराज गायकवाड़ की शतकीय पारी के बाद गेंदबाजों का कहर, रोमांचक मैच में भारत ने श्रीलंका को रौंदा

(जीएनएस)।

श्रीलंका में खेली जा रही त्रिकोणीय वनडे सीरीज के मुकाबले में भारत ए ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और निर्धारित 50 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 277 रन बनाए। टीम की ओर से ऋतुराज गायकवाड़ ने शानदार शतकीय पारी खेली, जबकि कप्तान तिलक वर्मा ने भी जिम्मेदारी भरी अर्धशतकीय पारी खेलकर टीम को मजबूत स्कोर तक पहुंचाया। जवाब में खेलते हुए श्रीलंकाई टीम स्कोर के करीब जाकर मैच हार गई।

भारत ए की शुरूआत हालांकि उम्मीद के मुताबिक नहीं रही। विकेटकीपर बल्लेबाज प्रभसिमरन सिंह सिर्फ 2 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इसके बाद युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी भी ज्यादा देर क्रीज पर नहीं टिक सके और 12 गेंदों में 14 रन बनाकर आउट हो गए। इस दौरान उन्होंने तीन चौके लगाए।

प्रियांश आर्या और ऋतुराज ने संभाली पारी

शुरूआती झटकों के बाद प्रियांश आर्या और ऋतुराज गायकवाड़ ने पारी को संभालने की कोशिश की। प्रियांश ने 32 गेंदों पर 32 रन बनाए, जिसमें चार चौके और एक छक्का शामिल था। हालांकि वह रन आउट होकर पवेलियन लौट गए।

इसके बाद ऋतुराज गायकवाड़ ने एक छोर संभाले रखा और बेहतरीन बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया। दाएं हाथ के बल्लेबाज ने 114 गेंदों का सामना करते हुए 101 रन बनाए। उनकी पारी में 6 चौके और 3 छक्के शामिल रहे। मुश्किल परिस्थितियों में खेली गई यह पारी भारत ए के लिए बेहद अहम साबित हुई।

कप्तान तिलक वर्मा ने निभाई जिम्मेदारी

ऋतुराज का साथ कप्तान तिलक वर्मा ने बखूबी निभाया। तिलक ने धैर्य के साथ बल्लेबाजी करते हुए 97 गेंदों में 60 रन बनाए। उन्होंने दो चौके और एक छक्का लगाया। दोनों बल्लेबाजों के बीच हुई महत्वपूर्ण साझेदारी ने भारत ए को बड़े स्कोर की ओर बढ़ाया।

निचले क्रम ने किया जोरदार फिनिश

अंतिम ओवरों में आयुष बडोनी और सूर्यांश शेडगे ने तेजी से रन जुटाए। बडोनी ने 18 गेंदों पर 24 रन बनाए, जबकि सूर्यांश शेडगे ने सिर्फ 14 गेंदों में नाबाद 26 रन ठोक दिए। उनकी पारी में एक चौका और दो छक्के शामिल रहे। अंत में अनुकूल रॉय 2 गेंदों में 1 रन बनाकर नाबाद लौटे।

भारत ए को अतिरिक्त रनों के रूप में 17 रन मिले, जिसमें 16 वाइड शामिल थे। श्रीलंका ए के गेंदबाजों ने दबाव बनाने की कोशिश जरूर की, लेकिन भारतीय बल्लेबाजों ने नियमित अंतराल पर साझेदारियां बनाकर स्कोर को 277 तक पहुंचा दिया।

लक्ष्य के करीब जाकर श्रीलंका की हार

278 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी श्रीलंका ए की टीम ने शानदार लड़ाई दिखाई, लेकिन जीत से महज 8 रन दूर रह गई। टीम 48.5 ओवर में 269 रन बनाकर ऑलआउट हो गई। सलामी बल्लेबाज निरोशन डिकवेला (47) और अविष्का फर्नांडो (45) ने तेज शुरूआत दी, जबकि सदीरा समरविक्रमा ने 46 रन बनाकर पारी को आगे बढ़ाया। कप्तान सहान अराचिगे ने सबसे बड़ी पारी खेलते हुए 72 गेंदों में 74 रन बनाए।

क्या है 12 रिजर्व सीटों का विवाद जिसके लिए पीओके में हो रही हिंसा? क्या है पाक के संविधान में?

(जीएनएस)।

पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (PoK) में सरकार और एक जमीनी आंदोलन के बीच टकराव अब इंटरनेशलन लेवल पर चर्चा का विषय बन गया है। हालात इतने गंभीर हो चुके हैं कि इस मुद्दे पर अब ब्रिटिश संसद में भी चर्चा हो रही है। हालिया हिंसा में कम से कम 7 नागरिकों की मौत हो चुकी है, जबकि बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन जारी हैं। ये हालात हाल के सालों में PoK के सबसे गंभीर राजनीतिक और सामाजिक टकरावों में से एक माना जा रहा है। जिसमें आम जनता और पाकिस्तान की पुलिस (जिसको आर्मी का पूरा सपोर्ट है) आमने-सामने हैं। इस पूरे आंदोलन के केंद्र में जम्मू-कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी (JAAC) है, जो शुरूआत में आर्थिक मुद्दों को लेकर बने एक जनआंदोलन के रूप में सामने आई थी, लेकिन समय के साथ इसकी मांगें संवैधानिक सुधारों तक पहुंच गई।

JAAC का गठन 2023 में बढ़ती महंगाई, बिजली की ऊंची कीमतों और आटे की लागत को लेकर हुए विरोध प्रदर्शनों के दौरान हुआ था। शुरूआत में संगठन का फोकस आर्थिक राहत और बुनियादी सुविधाओं पर था, लेकिन बाद में इसने राजनीतिक और संवैधानिक सुधारों की मांग भी उठानी शुरू कर दी। इसी कारण यह आंदोलन अब केवल महंगाई विरोधी अभियान नहीं रह गया, बल्कि ढङ्कङ की राजनीतिक व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठाने लगा है।

पिछले कई हफ्तों से तनाव बढ़ रहा था क्योंकि खअअउ ने 9 जून को बड़े प्रदर्शन का आ'ान किया था। यह प्रदर्शन PoK विधानसभा की 12 आरक्षित सीटों के खिलाफ था। ये सीटें उन कश्मीरी शरणार्थियों के लिए आरक्षित हैं जो 1947 के विभाजन के बाद भारतीय जम्मू-कश्मीर से पाकिस्तान में जाकर बस गए थे। खअअउ नेताओं का आरोप है कि इन सीटों के जरिए पाकिस्तान की बड़ी राजनीतिक पार्टियां मुजफ्फराबाद की राजनीति और सरकार गठन पर जरूरत से ज्यादा प्रभाव डालती हैं। संगठन का कहना है कि इससे स्थानीय लोगों की राजनीतिक ताकत कमजोर होती है।

PoK की विधानसभा में कुल 45 सदस्य होते हैं। इनमें से 33 सीटें PoK के भीतर के निर्वाचन क्षेत्रों से चुनी जाती हैं। 12 सीटें उन "जम्मू-कश्मीर शरणार्थियों" के लिए आरक्षित हैं, जो 1947 या बाद के संघर्षों के दौरान भारतीय जम्मू-कश्मीर से पाकिस्तान चले गए और अब पाकिस्तान के अलग-अलग प्रांतों में रहते हैं। दिलचस्प बात यह है कि इन 12 सीटों के मतदाता PoK में नहीं रहते, बल्कि पाकिस्तान के पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और अन्य इलाकों में बसे हुए हैं। इन 12 सीटों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र बनाए गए हैं। मतदान पाकिस्तान के मुख्य भूभाग में रहने वाले कश्मीरी शरणार्थी करते हैं।

'31 स्टार्टअप्स हजारों नए रोजगार पैदा करेंगे', मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कही बड़ी बात

(जीएनएस)।

वर्तमान समय में पंजाब नवीन विचारों, विशिष्ट सोच और उद्यमी युवाओं द्वारा लीक से हटकर पहलकदमियां करने के कारण विकास की नई कहानी रच रहा है, जिसकी वजह से राज्य देश भर में सबसे पसंदीदा स्टार्टअप स्थल के रूप में उभर रहा है जहां युवा अपने विचारों को व्यवसाय और रोजगार के अवसरों में बदल रहे हैं।

इस सोच की पैरवी करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आज 31 स्टार्टअप्स और उनके संस्थापकों को 1.07 करोड़ रुपए की सीड ग्रांट वितरित की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सफल उद्यमियों की अगली पीढ़ी न सिर्फ पंजाब से आए बल्कि पंजाब में अपनी कंपनियां भी स्थापित करे, जिससे राज्य के अंदर ही नौकरियों और कमाई के अवसर पैदा हों।

स्टार्टअप को पंजाब के भविष्य के आर्थिक विकास का मुख्य स्तंभ बताते हुए उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह वचनबद्ध है कि किसी भी शानदार उद्यम को वित्तीय सहायता की कमी के कारण छोड़ा न जाए।

'पंजाब स्टार्टअप और इंडस्ट्रियल पॉलिसी-2026'

मुख्यमंत्री ने कहा कि 'पंजाब स्टार्टअप और इंडस्ट्रियल पॉलिसी-2026' के तहत सीड ग्रांट को 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया गया है, जिसमें 7 स्टार्टअप्स को 5-5 लाख रुपये और 24 स्टार्टअप्स को 3-3 लाख रुपए की ग्रांट मिल रही है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि ये उद्यम रोजगार के हजारों अवसर पैदा करेंगे और युवाओं में नौकरियों की तलाश में विदेश जाने के रुझान को कम करने में मदद करेंगे।

भारत का स्टार्टअप हब बनने के रास्ते पर पंजाब

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि मुफ्त बिजली, किसानों को दिन में बिजली सप्लाई और कई अन्य सुधारों जैसी पहलकदमियों से यह पता चलता है कि कैसे नए विचार लोगों को सीधा लाभ पहुंचा सकते हैं। उन्होंने कहा कि उद्यमिता और नवाचार में मिल रहे भरपूर समर्थन के साथ पंजाब, भारत का स्टार्टअप हब बनने के रास्ते पर लगातार आगे बढ़ रहा है।

'पंजाब के उद्योग के लिए एक ऐतिहासिक दिन'

स्टार्टअप्स को सीड ग्रांट वितरित करने संबंधी समारोह के दौरान सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री

भगवंत सिंह मान ने कहा, "आज पंजाब के उद्योग के लिए एक ऐतिहासिक दिन है, खासकर हमारे युवा उद्यमियों के लिए जो नए विचारों के साथ अपना कारोबारी सफर शुरू कर रहे हैं। 31 स्टार्टअप्स को 1.07 करोड़ रुपए की सीड ग्रांट दी जा रही है। 7 स्टार्टअप्स को 5-5 लाख रुपए की ग्रांट मिल रही है, जबकि 24 स्टार्टअप्स को 3-3 लाख रुपए की ग्रांट मिल रही है। ये युवा उद्यमी अपने विचारों के माध्यम से सपनों को साकार कर रहे हैं और वे इस सहयोग के हकदार हैं।"

झाड़ू ने राजनीतिक व्यवस्था को साफ किया: सीएम भगवंत मान

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, "आम आदमी पार्टी (आप) खुद एक ऐसे विचार से पैदा हुई थी जब देश में परिवारवाद की राजनीति का दबदबा था और आम आदमी को अनदेखा कर दिया गया था। कई पहलुओं से 'आप' एक स्टार्टअप भी थी जिसने झाड़ू के अपने प्रतीक के साथ राजनीतिक व्यवस्था को साफ किया। 2022 के विधानसभा चुनाव में पंजाब के लोगों ने 7 पूर्व मुख्यमंत्रियों और उनके परिवारों को बाहर का रास्ता दिखाया और ईमानदार सरकार को मौका दिया। उस फैसले ने पंजाब को बदल दिया है और इसे देश का एक अग्रणी राज्य बना दिया है।"

'हमारे युवा पंजाब के भविष्य को नया रूप दे रहे'

वना को उजागर करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, "पंजाबी अपनी मेहनत, जज्बे और उद्यम के लिए दुनिया भर में जाने जाते हैं। उसी भावना से प्रेरित होकर हमारे युवा नए उद्यम शुरू कर रहे हैं और नए अवसर पैदा कर रहे हैं। वे सिर्फ कारोबार नहीं चला रहे, वे पंजाब के भविष्य को नया रूप दे रहे हैं।"

'कारोबार स्थापित करते हैं, रोजगार पैदा करते हैं'

पंजाबी मूल के सफल उद्यमियों के उदाहरण देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, "भारत और दुनिया भर में बहुत सी सफल कंपनियां पंजाबियों द्वारा स्थापित या सह-स्थापित की गई हैं। जोमैटो, ओला और फ्लिपकार्ट जैसी कंपनियां इसकी उदाहरण हैं कि कैसे पंजाबियों ने विश्व स्तर पर अपनी पहचान बनाई है। पंजाब हमेशा उद्यमियों की धरती रहा है। पंजाबी जहां भी जाते हैं, वे कारोबार स्थापित करते हैं, रोजगार पैदा करते हैं और अपनी अलग छाप छोड़ते हैं। हमारा लक्ष्य है कि सफल संस्थापकों की अगली पीढ़ी न सिर्फ पंजाब से आए बल्कि पंजाब में अपनी कंपनियां भी स्थापित करे।"

इनोवेशन इको-सिस्टम (नवीनतम प्रणाली) की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, "सीड मनी (स्टार्टअप के लिए सहायता राशि) प्रदान करने का उद्देश्य स्टार्टअप्स पर आने वाले शुरूआती बोझ को कम करना और उन्हें अपने विचारों को हकीकत में बदलने तथा आगे बढ़ने का भरोसा देना है। विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को नवाचार के केंद्र बनना चाहिए जहां विचार क्लासरूम से परे उत्पाद, सेवाएं, कंपनियां और समाधान की नींव बनते हैं।"

'इको-सिस्टम को सही ढंग से डिजाइन किया जाता है'

अपने विदेशी दौरों को याद करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि दक्षिण कोरिया के पैंगयो टेक्नो वैली और नीदरलैंड्स के वर्ल्ड हॉर्टी सेंटर में उन्होंने देखा कि कैसे एक योजनाबद्ध इनोवेशन इको-सिस्टम पूरे क्षेत्र को बदल सकता है।

इस मॉडल से पता लगता है कि जब इको-सिस्टम को सही ढंग से डिजाइन किया जाता है तो विचार विश्व स्तरीय कंपनियों की नींव बन सकते हैं। इसी तरह नीदरलैंड्स में वर्ल्ड हॉर्टी सेंटर के अपने दौरे के दौरान मैंने देखा कि कैसे इनोवेशन नई तकनीकों की टेस्टिंग, लागूकरण और व्यावसायीकरण के माध्यम से खेतीबाड़ी और बागबानी को बदल सकती है।"

हमारे किसान हमेशा प्रगतिशील रहे हैं- मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान

पंजाब की कृषि क्षमता के बारे में बात करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, "पंजाब में भविष्य का विकास उच्च-मूल्य वाली खेतीबाड़ी, एग्री-टेक, फूड प्रोसेसिंग, सुरक्षित खेती, कोल्ड चेन और एग्री-लॉजिस्टिक्स के माध्यम से होना चाहिए। हमारे किसान हमेशा प्रगतिशील रहे हैं और पंजाब सरकार उन्हें आधुनिक तकनीक, बेहतर बाजार और नए कारोबारी मॉडलों तक पहुंच प्रदान करने के लिए वचनबद्ध है।"

उप्रः बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि पर मुख्यमंत्री योगी समेत कई नेताओं ने श्रद्धांजलि दी

(जीएनएस)।

लखनऊ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, समाजवादी पार्टी (सपा) के अध्यक्ष अखिलेश यादव समेत कई प्रमुख नेताओं ने स्वतंत्रता सेनानी एवं जनजातीय गौरव के प्रतीक बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि पर मंगलवार को उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की।

योगी ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, "अंग्रेजी शासन के अन्याय के विरुद्ध जनजातीय स्वाभिमान को नई ऊर्जा एवं 'उलगुलान' के अमर उद्घोष से भारत के स्वाधीनता संघर्ष को नई दिशा देने वाले 'धरती आबा' भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि पर शत-शत नमन।"

उन्होंने कहा, "त्याग, तप और राष्ट्रनिष्ठा से आलोकित आपका जीवन भारत के लिए अमर प्रेरणा है।"

पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, "महान स्वतंत्रता सेनानी और जननायक भगवान बिरसा मुंडा जी की पुण्यतिथि पर शत-शत नमन।" उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने अपने संदेश में कहा, "महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, जनजातीय गौरव के प्रतीक एवं 'धरती आबा' भगवान बिरसा मुंडा जी के बलिदान दिवस पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि।"

मौर्य ने कहा, "जल, जंगल, जमीन और जनजातीय अस्मिता के सजग प्रहरी भगवान बिरसा मुंडा जी ने अन्याय तथा विदेशी शासन के विरुद्ध संघर्ष का बिगुल फूंककर आदिवासी समाज में स्वाभिमान व अधिकारों की चेतना जागृत की।"

उन्होंने कहा, "अल्पायु में ही मातृभूमि, समाज और संस्कृति की रक्षा के लिए दिया गया उनका सर्वोच्च बलिदान भारतीय इतिहास में सदैव अमर रहेगा। उनका साहस, नेतृत्व और जनसेवा का भाव आज भी हमें सामाजिक न्याय, स्वाभिमान और राष्ट्रहित के लिए समर्पित रहने की प्रेरणा देता है।"

उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, "भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के अमर सेनानी, आदिवासी संस्कृति और अस्मिता के रक्षक एवं उन्नायक, अद्भुत समाज सुधारक तथा महान क्रांतिकारी भगवान बिरसा मुंडा जी की पुण्यतिथि पर उन्हें कोटि-कोटि नमन।"

कांग्रेस की उत्तर प्रदेश इकाई के अध्यक्ष और प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री अजय राय ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, "धरती आबा बिरसा मुंडा जी के बलिदान दिवस पर कोटिशः नमन।"

बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर, 1875 को वर्तमान झारखंड में हुआ था।

उन्होंने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध आदिवासी आंदोलन का नेतृत्व किया और 19वीं सदी के उत्तरार्द्ध में हुए ऐतिहासिक आदिवासी विद्रोह 'उलगुलान' के वह प्रमुख नायक थे।

मुंडा का नौ जून, 1900 को निधन हुआ था। आदिवासी समाज के अधिकारों, स्वाभिमान और सांस्कृतिक अस्मिता की रक्षा के लिए उनके संघर्ष को भारतीय इतिहास में विशेष स्थान प्राप्त है।

जिनका भी भारतीय है, उनको भगवान राम से प्रेम : सीएम योगी

श्री राम कथा महोत्सव के समापन कार्यक्रम में पहुंचे योगी, लव जिहाद पर चेताया

(जीएनएस)।

लखनऊः मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को कहा कि जिसमें भी भारत का डीएनए है, वह किसी न किसी जरिए से भगवान राम के आदर्शों को जरूर मानता है. कुछ राजनीतिक लोगों को छोड़ दीजिए तो किसी को भी भगवान राम से कोई गुरेज नहीं है.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में चल रहे 9 दिवसीय श्री राम कथा महोत्सव के समापन कार्यक्रम में कहा कि मयार्दा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का नाम ही वह अद्भुत शक्ति है, जो उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक पूरे भारत को एक सूत्र में बांध सकता है. मुख्यमंत्री ने राम मंदिर आंदोलन का जिक्र करते हुए कहा कि लगभग 500 वर्षों तक चले आंदोलन के बाद वर्ष 2019 में सर्वोच्च न्यायालय ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया. अदालत ने स्पष्ट किया कि जहां रामलला विराजमान हैं, वही राम जन्मभूमि है. उन्होंने बताया कि न्यायमूर्ति ने रामभद्राचार्य के बयान को उद्धृत करते हुए कहा कि सनातन धर्मावलंबियों पर सदियों से कितना अत्याचार हुआ है, यह सुनकर अदालत भी प्रभावित हुई.

रामायण से समसामयिक सबक

योगी आदित्यनाथ ने रामायण की घटनाओं को वर्तमान परिस्थितियों से जोड़ते हुए कहा कि जब भी

नकारात्मक ताकतें वर्चस्व पाती हैं, तो वे उसी प्रकार विनाश करती है, जैसा रावण के काल में होता था. उन्होंने शिक्षण संस्थानों को बंजर बनाने की तुलना खर-दूषण और ताड़का से की. मुख्यमंत्री ने माता जानकी के अपहरण का उदाहरण देते हुए कहा कि भगवान राम ने उत्तर और दक्षिण को जोड़कर नारी गरिमा की रक्षा का आदर्श प्रस्तुत किया.

लव जिहाद का मुद्दा

सीएम ने इसे लव जिहाद जैसी घटनाओं को चेतावनी के रूप में याद करने की बात कही. उन्होंने आश्चर्य व्यक्त किया कि केरल उच्च न्यायालय ने 2009 और 2011 में इस मुद्दे पर गहरी चिंता जताई थी, फिर भी देश में इसे गंभीरता से नहीं लिया गया. यह धार्मिक जनसांख्यिकी बदलने की साजिश का हिस्सा है. हमने 2020 में उत्तर प्रदेश में सख्त कानून बनाया, लेकिन अब व्यापक जनजागरूकता की जरूरत है," उन्होंने जोर दिया.

लैंड जिहाद पर क्या कहा

सीएम योगी ने लैंड जिहाद का मुद्दा भी उठाया. उन्होंने कहा कि खर-दूषण, मारीच और सुबाहु जैसे पात्र भी लैंड जिहाद से जुड़े थे. खाली जमीन देखकर जबरन कब्जा करना उसी मानसिकता का हिस्सा है. उन्होंने स्पष्ट कहा, 'भारत की धरती उन आक्रांताओं के लिए धर्मशाला नहीं हो सकती, जिनमें भारत के प्रति आस्था नहीं है, निष्ठा नहीं है और जो इस देश के संस्कारों का सम्मान नहीं करते.' मुख्यमंत्री ने कहा कि नकारात्मक ताकतें हर युग में आती रहेंगी, लेकिन समाज को एकजुट होकर तैयार रहना चाहिए. राम कथा हमें यही संदेश देती है कि सत्य और धर्म की रक्षा के लिए निरंतर प्रयासरत रहना चाहिए. कार्यक्रम में राम कथा वाचक और भक्तों की बड़ी संख्या में उपस्थिति रही. समापन समारोह में सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए.

रामभद्राचार्य से बोले योगी, आपके प्रिय आम लाया हूँ

भारतीय जनता पार्टी के लखनऊ उत्तर क्षेत्र से विधायक डॉ. नीरज बोरा की ओर से आयोजित राम कथा समारोह के अंतिम दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं. यहां वे गुरु रामभद्राचार्य से मिले. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रामभद्राचार्य को अंग वस्त्र उदय और आम भेंट किए. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनसे कहा कि आपको देवताओं में राम और फलों में आम प्रिय है, आपके लिए लाया हूं.

यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा के फर्जी वीडियो वायरल करने में लखनऊ में केस, अलीगढ़ और आजमगढ़ में भी एफआईआर

यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा के फर्जी और भ्रामक वीडियो बनाकर वायरल करने के मामले में पुलिस ने सख्त एक्शन लेते हुए मुकदमा दर्ज किया है। वहीं, अलीगढ़ से एक मुन्ना भाई को भी पकड़ा है।

(जीएनएस)।

लखनऊः उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी (सिपाही) सीधी भर्ती-2025 की लिखित परीक्षा आयोजित की जा रही है। यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा में अफवाह और गड़बड़ी पर एक्शन हो रहे हैं। सोशल मीडिया और यूट्यूब चैनल पर भ्रामक जानकारी फैलाने के मामले में एफआईआर दर्ज की गई है।

उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की ओर से जारी प्रेस नोट के अनुसार, यूट्यूब चैनल टारगेट सेलेक्शन पर भ्रामक और तथ्यहीन वीडियो बनाकर वायरल करने के मामले में लखनऊ के हुसैनगंज थाने में विभिन्न धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है। इंस्टाग्राम पर आईडी से भ्रामक वीडियो पोस्ट किए गए। इनके खिलाफ आजमगढ़ कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया है।

अलीगढ़ में पकड़ा गया मुन्ना भाई

इसके अलावा अलीगढ़ जिले के रतनप्रेम डीएवी बालिका इंटर कॉलेज में विकास कुमार नाम का मुन्ना भाई पकड़ा गया है। फिरोजाबाद का रहने वाला विकास कुमार परीक्षार्थी हरिओम कुमार की जगह परीक्षा दे रहा था। इसके पास से फर्जी आधार कार्ड बरामद हुआ है। थाना क्वार्सी में विभिन्न धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है। फेसबुक यूजर तनिष्क चौधरी पर भ्रामक और तथ्यहीन वीडियो वायरल करने के मामले में लखनऊ के हुसैनगंज थाने में केस दर्ज किया गया है।

यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा चल रही

बता दें कि यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा सोमवार को प्रदेश के सभी 75 जिलों के 1,183 परीक्षा केंद्रों पर दो पालियों में शांतिपूर्ण एवं सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न हुई। आज भी (मंगलवार) पुलिस भर्ती परीक्षा आयोजित की जा रही है। बुधवार को भी परीक्षा आयोजित होगी। वहीं, पहले दिन आठ जून को लखनऊ में डॉक्टर खेड़ा में ऑटो चालक ने दो महिला पुलिस भर्ती अभ्यर्थियों से दुष्कर्म का प्रयास किया। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इनकी पहचान हरदोई जिले के कछौना निवासी हसीब के रूप में हुई है।

योगी बोले- मारीच और सुबाहु लैंड जिहादी थेःराम लव जिहाद रोकने के लिए आदर्श उदाहरण, रामभद्राचार्य की कथा में पहुंचे

(जीएनएस)।

सीएम योगी मंगलवार को लखनऊ में जगदुरु रामभद्राचार्य की श्रीरामकथा में पहुंचे। उन्होंने कहा- प्रभु श्रीराम ने नारी गरिमा के लिए काम किया। यह आज के समय में लव जिहाद रोकने के लिए आदर्श उदाहरण है। शायद ही कोई ऐसा भारतीय हो, जिसके डीएनए में भारत हो और वह श्रीराम को न मानता हो।

सीएम ने कहा- याद करिए रावण का राज्य था। खर और दूषण पूरे दंडकारण्य में कब्जा जमाए थे। ताड़का बक्सर तक आ गई थी। ये सब मिलकर पूरा उजाड़ मचाए हुए थे। जब भी नकारात्मक ताकतें आती हैं तो उजाड़ ही करती हैं।

उन्होंने कहा- खर-दूषण और मारीच-सुबाहु क्या कर रहे थे? वो भी रावण के साथ लैंड जिहाद के अभियान में जुड़े हुए थे। साधु-संतों को उनकी जगह से हटाकर लैंड जिहाद करते थे। रामकथा केवल सुनने का विषय नहीं है। इसे सुनकर समझना होगा।

सीएम ने जगदुरु रामभद्राचार्य को शॉल ओढ़ाया। इस दौरान जगदुरु 1 मिनट तक सीएम योगी के कान में कुछ कहते रहे। फिर पोटली से कुछ निकालकर सीएम को भेंट दिया। राम कथा का आज 9वां और आखिरी दिन है।

1- जिसने राम का द्रोह किया, वह मिट गया योगी ने कहा- नकारात्मक ताकतें हर कालखंड में आएंगी, लेकिन सज्जन शक्ति को इनका डटकर मुकाबला करना होगा। राम जब पहली बार घर से निकले तो उन्हें सबसे पहले ताड़का मिली। वह रावण से प्रेरित थी। गलत को गलत ही मिलते हैं। जिसने भी राम को अपने जीवन का आदर्श बनाया, उसका कल्याण हुआ। जिसने राम का द्रोह किया, उसको इस धरती पर कोई जगह नहीं मिली।

मारीच, रावण उच्च कुल और श्रेष्ठ व्यवस्था में जन्म लेते हैं और पशुवत मारे जाते हैं। क्योंकि, राम के साथ द्रोह करते हैं। हमारे पवनसुत हनुमानजी हैं, विभीषण हैं... इनको भले ही जन्म के समय सामान्य जीवन मिला। लेकिन, राम की संगत का असर हुआ कि ये पूज्य हो गए। हम सुबह जो 7 नाम लेते हैं, उनमें विभीषण का भी नाम है। हमारे यहां हर समस्या का समाधान हनुमान चालीसा है।

2- अगर आस्था नहीं, तो यह धरती धर्मशाला नहीं सीएम ने कहा- जो भारत के प्रति निष्ठा नहीं रखते, जिनकी भारत के प्रति आस्था नहीं है, भारत के संस्कारों का सम्मान नहीं कर सकते, उन लोगों के लिए भारत की धरती धर्मशाला नहीं हो सकती। इस संकल्प के साथ हम सब आगे बढ़ेंगे। संत शक्ति सबको एकजुट कर आगे ले जाना चाहती है।

उन्होंने कहा- कोई धर्म के नाम पर, कोई जाति के नाम पर बांटने का प्रयास करेगा, लेकिन हम सबको कथा के उस मर्म को समझना पड़ेगा, जो यहां पर व्यासपीठ से जगदुरु ने समझाने का प्रयास किया। हमारे जो आदर्श हैं, उनके अनुसार जीवन जीने का प्रयास करें। हम शिव और राम की पूजा करते हैं तो अपना जीवन उनके आदर्श पर जीएं।

सीएम ने कहा- जिसने भी राम को अपने जीवन का आदर्श बनाया, उसका कल्याण हुआ।

सीएम ने कहा- जिसने भी राम को अपने जीवन का आदर्श बनाया, उसका कल्याण हुआ।

3- शायद ही कोई भारतीय हो, जो श्रीराम को न मानता हो सीएम ने कहा- रामजन्मभूमि को सभी पूज्य संतों ने अपने जन्म-मरण का विषय बना दिया था। पूज्य संतों ने इसलिए नहीं किया था कि उन्हें कुछ लाभ मिले। उन्होंने श्रीराम के लिए किया। एक नाम उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम तक जोड़ सकता था। एक लंबे समय तक उनके लिए आंदोलन चला। 491 वर्षों तक रामजन्मभूमि के लिए किसी न किसी रूप में आंदोलन चलता रहा।

4- जो काम तुलसीदास ने किया, वही रामभद्राचार्य कर रहे योगी ने कहा- मध्यकाल में तुलसीदास ने जनचेतना जागृत की, समाज को एकजुट करने की, विदेशी आक्रांतों के सामने आने की, प्रभु राम के प्रति भक्ति का संदेश देकर पूरे उत्तर भारत को एकता में जोड़ने का काम किया। वही काम आज जगदुरु रामभद्राचार्य कर रहे हैं। वह आम व्यक्ति नहीं, वह जगदुरु हैं।

उन्होंने उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश के पहले दिव्यांग विश्वविद्यालय की स्थापना चित्रकूट में करवाई है। वह उस विश्वविद्यालय के अभी भी कुलाधिपति हैं। इसके बावजूद वह भक्तों का सम्मान रखने के लिए रामकथा सुनाते हैं। इसके पीछे एक ही उद्देश्य होता है कि मयार्दा पुरुषोत्तम भगवान राम के आचरणों का कोई अनुसरण कर ले, तो देश का बहुत बड़ा कल्याण होगा।

'भारतीय संस्कृति में वाइफ नहीं, धर्मपत्नी है':लखनऊ में रामभद्राचार्य बोले- महिलाओं के बिना समाज की कल्पना अधूरी है

रामभद्राचार्य महाराज ने सोमवार को लखनऊ में कहा- भारतीय संस्कृति में पत्नी सिर्फ जीवनसाथी नहीं होती, बल्कि धर्म निभाने वाली साथी मानी जाती है। मां का स्थान बहुत ऊंचा होता है और उसे पिता से भी बड़ा दर्जा दिया गया है। इस कथा के दौरान उन्होंने यह भी कहा कि महिलाएं परिवार, समाज और देश के निर्माण में अहम भूमिका निभाती हैं और उनके बिना समाज की कल्पना अधूरी है।

पीजीआई में धर्मांतरण! इरशाद अली पर किडनैप कर सीरिया ले जाने के आरोप

(जीएनएस)।

लखनऊ में धर्मांतरण के आरोपों और युवती के लापता होने से जुड़े दो मामलों ने सनसनी फैला दी है. पीजीआई क्षेत्र में एक युवती के गायब होने पर परिजनों ने अपहरण और धर्मांतरण की साजिश का आरोप लगाया है, जबकि पारा क्षेत्र में युवती ने शादी का झांसा देकर शोषण और धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने की शिकायत दर्ज कराई है.

उत्तर प्रदेश के लखनऊ में केजीएमयू मेडिकल कालेज के बाद अब पीजीआई परिसर में धर्मांतरण के आरोपों और एक युवती के लापता होने से जुड़े दो अलग-अलग मामलों ने पुलिस प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है. दोनों मामलों में गंभीर आरोप लगाए गए हैं, जिनकी जांच पुलिस द्वारा की जा रही है. अधिकारियों का कहना है कि सभी तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर

आगे की कार्रवाई की जाएगी.

पहला मामला पीजीआई थाना क्षेत्र का है. एसजीपीजीआई आवासीय परिसर में रहने वाले शख्स ने अपनी 21 साल की बेटी के लापता होने की शिकायत दर्ज कराई है. परिजनों के अनुसार अन्नू 21 मई 2026 को नौकरी के सिलसिले में तेलीबाग स्थित बी-2 मार्केट गई थी, लेकिन इसके बाद घर वापस नहीं लौटी. परिवार का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज में युवती की गतिविधियां दर्ज हैं, जिन्हें जांच के लिए सुरक्षित रखा गया है.

परिजनों ने इरशाद अली नामक युवक पर बेटी को अपने साथ ले जाने का आरोप लगाया है. शिकायत में यह भी कहा गया है कि आरोपी का परिवार से पहले से परिचय था और वह घर आता-जाता था. पीड़ित परिवार का आरोप है कि पूर्व में भी संबंधित व्यक्ति के खिलाफ शिकायत की गई थी, लेकिन प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई. परिवार ने पीजीआई के एक डॉक्टर पर भी आरोपी की मदद करने का आरोप लगाया है. हालांकि आरोपों की आधिकारिक पुष्टि फिलहाल नहीं हुई है और पुलिस जांच जारी है.

हापुड़ में दिल्ली-लखनऊ हाईवे पर बेलगाम ट्रैक्टर की चपेट में आकर युवक की मौत, बाइक से जा रहा था पिलखुवा

हापुड़ में दिल्ली-लखनऊ हाईवे पर सरुरपुर गांव के पास एक बेलगाम ट्रैक्टर की टक्कर से बाइक सवार सत्यप्रकाश की मौत हो गई। सत्यप्रकाश अपने भतीजे के साथ बदा ...और पढ़ें

(जीएनएस)।

हापुड़, सरुरपुर गांव के सामने मंगलवार की सुबह बेलगाम ट्रैक्टर की टक्कर से बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई।

कोतवाली क्षेत्र स्थित दिल्ली लखनऊ हाईवे पर सरुरपुर गांव के सामने मंगलवार की सुबह बेलगाम ट्रैक्टर की टक्कर से बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई, जबकि एक युवक दुर्घटना में बाल-बाल बच गया है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

गढ़मुक्तेश्वर कोतवाली क्षेत्र स्थित दिल्ली लखनऊ हाईवे पर सरुरपुर गांव के निकट सड़क दुर्घटना में बंदायू के एक युवक की मौत हो गई। स्वजन ने बताया कि बंदायू के थाना बिसौली के निजामुद्दीन गांव के रहने वाले सत्यप्रकाश उम्र करीब 32 वर्ष

पिलखुवा स्थित एक प्राइवेट कंपनी में कार्य करते थे। उन्हीं के साथ उनका भतीजा सुमित भी कार्य करता है।

वह मंगलवार की सुबह सत्यप्रकाश एवं सुमित बाइक से बंदायू से पिलखुवा जा रहे थे। सरुरपुर गांव के सामने वह टॉयलेट करने के लिए रुके थे। इस बीच सत्यप्रकाश टॉयलेट करके वापस बाइक पर आकर बैठ गए, जबकि सुमित टॉयलेट कर रहा था। इसी दौरान पीछे से आए (पशुओं के रातब) से भरे एक बेलगाम ट्रैक्टर ट्राली ने बाइक में टक्कर मार दी।

ट्रैक्टर के नीचे बाइक आने से सत्यप्रकाश काफी दूर तक उसके नीचे घिसटता चला गया। इसके बाद टैक्टर हाईवे के किनारे खेत में जाकर रुका। ट्रैक्टर के नीचे घिसटने से बाइक सवार सत्यप्रकाश की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। दुर्घटना के बाद चालक ट्रैक्टर को छोड़कर मौके से फरार हो गया। सुमित ने इस बात की सूचना पुलिस को दी।

स्वजन ने बताया कि मृतक के छोटे- छोटे तीन बच्चे हैं, जिसमें दो बेटी तथा एक सात माह का बेटा है। घटना की सूचना मिलने के बाद स्वजन में हाहाकार मच गया। कोतवाली प्रभारी देवेंद्र सिंह बिष्ट ने बताया कि स्वजन की तहरीर पर पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजते हुए मामले की जांच शुरू कर दी है।

लखनऊ के इकाना स्टेडियम में अनुबंध शर्तों का उल्लंघन! एलडीए ने जांच की कमेटी बनाई, जांच समिति 15 दिन के अंदर देगी रिपोर्ट, इसके बाद ही तय होगी कार्रवाई.

(जीएनएस)।

लखनऊः लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) ने अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम की जांच के लिए एक समिति बना दी है. आरोप है कि स्टेडियम प्रशासन एलडीए से हुए अनुबंध की शर्तों का ठीक से पालन नहीं कर रहा है. एलडीए ने समिति से 15 दिन के अंदर रिपोर्ट मांगी है.

इकाना स्टेडियम को सरकारी जमीन पर अनुबंध के आधार पर चलाया जा रहा है. अनुबंध में कई शर्तें तय हैं. जैसे समय-समय पर हाउस टैक्स जमा करना, साफ-सफाई रखना, कचरा निपटान की व्यवस्था करना और अवैध व्यावसायिक गतिविधियां न चलाना. जांच में सामने आया कि इनमें से कई शर्तों का उल्लंघन हुआ है.

पिछले दिनों लखनऊ नगर निगम ने भी स्टेडियम प्रशासन को 28.42 करोड़ रुपये का हाउस टैक्स बकाया होने का नोटिस भेजा था. बार-बार नोटिस देने के बाद भी टैक्स जमा न होने पर नगर निगम ने सीलिंग की कार्रवाई की चेतावनी दी थी. इसके अलावा दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट के बाद स्टेडियम और आसपास कचरे का अंबार लग गया था. कचरा प्रबंधन के नियमों का पालन न करने पर नगर निगम ने 5 लाख रुपये का जुमार्ना

लगाया था.

अनुबंध में स्टेडियम प्रबंधन को साफ-सफाई, पार्किंग व्यवस्था और पर्यावरण संबंधी नियमों का पालन करना जरूरी है लेकिन शिकायतें मिलने के बाद एलडीए ने मामले को गंभीरता से लिया और तीन सदस्यीय जांच समिति बना दी. समिति यह देखेगी कि अनुबंध की कौन-कौन सी शर्तें तोड़ी गई हैं और स्टेडियम प्रशासन से क्या कार्रवाई की जाए.

यह पहली बार नहीं है जब इकाना स्टेडियम विवादों में आया हो. राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी एनजीटी ने भी भूजल दोहन और पर्यावरण नियमों के पालन न करने पर इकाना समेत देश के 6 बड़े स्टेडियमों को नोटिस भेजा था. एनजीटी ने पूछा था कि आदेश न मानने पर स्टेडियम की गतिविधियां क्यों न रोकी जाएं?

एलडीए के उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार का कहना है कि सरकारी जमीन पर बने किसी भी प्रतिष्ठान को नियमों का पालन करना ही होगा. अगर जांच में अनियमितता पाई जाती है तो अनुबंध के हिसाब से सख्त कार्रवाई की जाएगी. इसमें जुमार्ना लगाना, सीलिंग करना या अनुबंध रद्द करना भी शामिल हो सकता है.

इकाना स्टेडियम के जनसंपर्क अधिकारी का कहना

इस मामले में इकाना स्टेडियम के जनसंपर्क अधिकारी गौरव ने बताया कि एलडीए अधिकारियों से हमने पुष्टि की है कि लखनऊ भर में अनेक इमारतों, परियोजनाओं, होटलों और अन्य प्रतिष्ठानों का सर्वेक्षण करने के लिए संबंधित अधिकारियों की एक समिति गठित की गई है. इस सर्वेक्षण का उद्देश्य संबंधित संपत्तियों की सुविधाओं और अनुपालन स्थिति का आंकलन करना तथा उसके अनुसार रिपोर्ट प्रस्तुत करना है. यह स्पष्ट किया जाता है कि इस समिति का गठन लखनऊ की कई परियोजनाओं और संपत्तियों के लिए किया गया है, न कि विशेष रूप से इकाना के लिए है. इकाना भी इसमें शामिल है.

कई अंतरराष्ट्रीय मैच मैच हो चुके हैं

इकाना स्टेडियम लखनऊ सुपर जायंट्स का होम ग्राउंड है और यहां आईपीएल समेत कई अंतरराष्ट्रीय मैच हो चुके हैं. ऐसे में स्टेडियम की जांच से क्रिकेट फैंस भी चिंतित हैं. हालांकि एलडीए का कहना है कि जांच का मकसद स्टेडियम को बंद करना नहीं, बल्कि नियमों का पालन करवाना है.

लखनऊ में नर्स को ट्रैक्टर-ट्रॉली ने कुचलाःड्यूटी से लौट रही थी युवती, जॉगर्स चौराहे पर सड़क पार करते समय हादसा

लखनऊ के दुबग्गा इलाके में मंगलवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसे में 26 वर्षीय नर्स की मौत हो गई। ड्यूटी खत्म कर घर लौट रही युवती को मौरंग से लदी ट्रैक्टर-ट्रॉली ने टक्कर मार दी। हादसे के दौरान ट्रॉली पलट गई और युवती उसके नीचे दब गई। गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

मृतका की पहचान साधना (26) पुत्री राम विशुन निवासी पनापुर कलां लगलेसरा, जनपद उन्नाव के रूप में हुई है। वह दुबग्गा स्थित विकल्प अस्पताल के नर्सिंग विभाग में कार्यरत थीं।

पैदल सड़क पार कर रही थी

पुलिस के मुताबिक, मंगलवार सुबह करीब 8:30 बजे शिफ्ट बदलने के बाद साधना पैदल अपने घर जा रही थीं। जॉगर्स चौराहे पर सड़क पार करते समय मौरंग से लदी ट्रैक्टर-ट्रॉली (नंबर वढ32छढ1910) की चपेट में आ गईं। टक्कर लगते ही ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलट गई और साधना उसके नीचे दब गईं।

इलाज के दौरान दम तोड़ा

हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने तत्काल राहत कार्य शुरू कर युवती को बाहर निकाला और उपचार के लिए विकल्प अस्पताल पहुंचाया। हालांकि सिर और पैरों में गंभीर चोटें आने के कारण उनकी जान नहीं बच सकी। डॉक्टरों ने इलाज के दौरान उन्हें मृत घोषित कर दिया।

सूचना मिलते ही दुबग्गा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भरने की कार्रवाई शुरू कर दी है। शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा जा रहा है।

पुलिस का कहना है कि दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है। ट्रैक्टर-ट्रॉली को कब्जे में ले लिया गया है और मामले में आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। हादसे के बाद मृतका के परिवार को सूचना दे दी गई है।